राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 259 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार,18 मार्च 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

भाजपा सांसद शर्मा दिल्ली में मृत पाए गए

नई दिल्ली, (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा बुधवार को यहां अपने नॉर्थ एवेन्यू आवास में मृत पाए गए। श्री शर्मा 63 वर्ष के थे। पुलिस के अनुसार श्री शर्मा के एक स्टाफ सदस्यों ने फोन कर इसकी जानकारी दी जिसके बाद एक टीम उनके आवास पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि उनकी टीम ने आवास पर पहुंचने के बाद देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था और श्री शर्मा मृत अवस्था में थे।

चार करोड़ एससी, एसटी को मिलेगा वजीफा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने अजा-जजा (एससी- एसटी) के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की राशि काफी बढ़ा दी है जिससे अब करीब चार करोड़ छात्र-छात्राओं को वजीफा मिल सकेगा। श्री कटारिया ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पहले एक ऐसे फार्मूले के तहत एससी-एसटी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी जिससे एक हजार करोड़ रुपए ही वजीफे के रूप में उन्हें दिये जा सकते थे लेकिन अब उस फार्मूले को बदल दिया गया जिससे इन विद्यार्थियों को बड़ी राशि इस मद में दी जा सकेगी।

250 किसानों की मौत पर चुप्पी क्यों: मलिक

जयपुर, (एजेंसी)। बीते तीन महीनों से चल रहे किसान आन्दोलन पर अब मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नेताओं के रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मलिक डीडवाना से दिल्ली जाते वक्त झुंझुनूं में कुछ देर के लिए रुके थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि, किसान आदोलन जितना भी लम्बा चलेगा, देश का उतना ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि यहां एक कुतिया मर जाती है तो नेताओं का शोकसंदेश आ जाता है। लेकिन आंदोलन करते-करते हमारे 250 से ज्यादा किसान मर गए, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा।

एक और सरकारी कंपनी पर लटका ताला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। एक और सरकारी कंपनी को बंद करने के लिए केंद्र ने मुहर लगा दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लंबे समय से घाटे में चल रहे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचएचईसी) को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचएचईसी) को बंद करने की स्वीकृति दे दी है।

जयपुर इंडिगो फ्लाइट में जन्मी बच्ची

जयपुर, (एजेंसी)। बेंगलुरु से जयपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बुधवार सुबह एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। फ्लाइट में मौजूद एक महिला डॉक्टर ने इंडिगो के क्रू मेंबर्स की मदद से सफल डिलीवरी कराई। फिलहाल, महिला व नवजात की हालात सुरक्षित और स्थिर है। एयरलाइन के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-469 ने सुबह 5.45 पर बेंगलुरु से उड़ान भरी थी। इसे 8 बजे जयपुर पहुंचना था। सीट नंबर 2-ए पर बैठी ललिता नाम की महिला को फ्लाइट में अचानक लेबर पेन शुरू हुआ, जिसके बाद क्रू मेंबर ने डिलेवरी करवाई।

मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी बोले- हमें कोरोना वायरस को फिर से फैलने से रोकना होगा

आरटी-पीसीआर टेस्ट को 70 फीसद करने की जरूरत

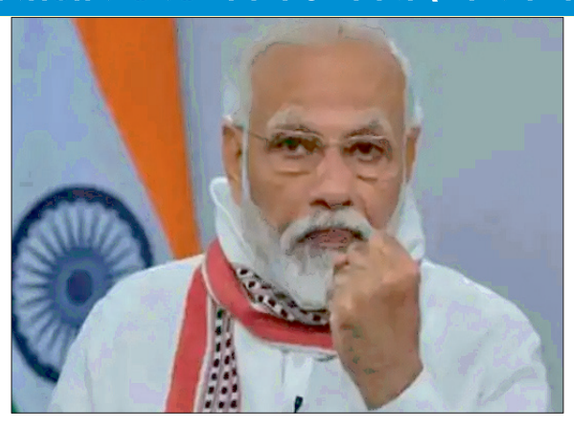

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों संग बैठक की। हालांकि बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें हर हाल में कोरोना महामारी को हराना होगा और इसके लिए मास्क को लेकर गंभीरता अभी भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन की बर्बादी की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन प्रभावी हथियार है।

मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को एक साल से ज्यादा हो रहा है। भारत के लोगों ने कोरोना का जिस प्रकार सामना हो रहा है, उसे लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं।आज देश में 96 प्रतिशत से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। मृत्यु दर में भी भारत सबसे कम दर वाले देशों में है। कुछ राज्यों में केसों की संख्या बढ़ रही है। देश के 70 जिलों में ये वृद्धि 150 प्रतिशत से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना की इस उभरती हुई दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। इसके लिए हमें त्वरित और निर्णायक कदम उठाने होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उससे आया आत्मविश्वास, लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। 'टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट' को लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70 प्रतिशत से ऊपर रखना बहुत अहम है।

बता दें कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण को देखते हुए पुणे, नागपुर और औरंगाबाद ने नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। वहीं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भोपाल और इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लागू किया है।

कोविड-19 महामारी ने दिखा दिया कि किसी भी संघर्ष में दुनिया कैसे एकजुट हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि महामारी से मिले सबक को नहीं भुलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 महामारी ने हमें सिखाया कि आपस में जुड़े और एक दूसरे पर आश्रित दुनिया में गरीब-अमीर, पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर सभी देश वैश्विक आपदाओं के प्रभाव से इम्यून हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, एक हाथ्न पर महामारी ने हमें दिखाया है कि दुनिया में आपदा का प्रभाव कैसे तुरंत फैल सकता है। वहीं दूसरी ओर इससे पता चला कि दुनिया कैसे इस खतरे के खिलाफ एकजुट हो संघर्ष के लिए खड़ी है। महामारी ने हमें यह दिखा दिया कि वैश्विक चुनौतियों से सामना करने के क्रम में इनोवेशन कहीं से भी आ सकती है। अन्य सदस्य देशों व संगठनों के साथ मिलकर CDRI तीन दिनों के लिए इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है जो 17 से 19 मार्च तक चलेगा।

राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्र की पार्टनरशिप CDRI है। इसका मकसद जलवायु के लिए नई अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना और सतत विकास के समर्थन में आपदा जोखिमों को कम करना है।

ग्वालियर में वायुसेना का मिग विमान गिरा, पायलट की मौत

ग्वालियर (एजेंसी)।

एयरफोर्स का मिग-21 बायसन लड़ाकू विमान बुधवार को टेकआफ के दौरान क्रैश हो गया। विमान में मौजूद ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता शहीद हो गए। विमान कांबेट ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भर रहा था और अचानक हादसा हो गया।

हादसे को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने गहरा शोक जताया और इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स का सेंट्रल इंडिया का ग्वालियर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस है। यहां प्रशिक्षण अभ्यास पर जाने से पहले विमान की रिफ्यूलिंग की गई थी। जैसे ही विमान टेक ऑफ हुआ तो प्लेन क्रैश हो गया। जिसमें ग्रुप कैप्टन शहीद हो गए। एयरफोर्स मध्य क्षेत्र के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शांतनु सिंह ने बताया कि विमानतल पर मिग-21 बायसन को ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता ने जैसे ही टेकऑफ किया हादसा हो गया, जिसमें ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता शहीद हो गए हैं। हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। फाइटर प्लेन के क्रैश होने के बाद एयरफोर्स ने नगरनिगम से फायरब्रिगेड भी बुलाई।

टॉप फाइटर कैप्टन थे गुप्ता- ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता ऑफिसर मिग-21 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। एयरफोर्स की टीएसीडीई विंग यानि टैक्टिक्स एंड एयर कांबेट डेवलपमेंट एस्टेबलिशमेंट एरियल कांबेट ट्रेनिंग देती है और यह एयरफोर्स के टॉप एक फीसद फाइटर पायलटों को ही दी जाती है। इसी में ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता भी शामिल थे। पहले यह टीएसीडीई जामनगर में स्थित थी लेकिन वर्ष 2000 में यह ग्वालियर एयरबेस स्टेशन शिफ्ट कर दी गई। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता की मौत एयरफोर्स के लिए बड़ी क्षति है।

मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने जताया शोक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर के समीप वायुसेना के एक लड़ाकू विमान मिग 21 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पायलट ए गुप्ता के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान देने और परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की है। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्रुप कैप्टन के निधन पर दुख जताया।

पीएम मोदी ने वैक्सीन के वेस्टेज पर नाराजगी जताई : डा. वीके पॉल

नई दिल्ली । देश में बढ़ते कोरोना मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद सक्रिय मामले 2 प्रतिशत हैं और मृत्यु दर 2 प्रतिशत से कम है। पूरे देश में क्युमुलेटिव पॉजिटिव रेट 5 प्रतिशत से कम हो गई है और पिछले एक सप्ताह में ये 3 प्रतिशत है। सभी सक्रिय मामलों का 60 फीसद महाराष्ट्र में केंद्रित है। उन्होंने कहा कि नए कोरोना मामलों का निम्नतम बिंदु 9 फरवरी था। आज नए कोरोना के मामलों में सप्ताह की वृद्धि लगभग 43 फीसद और नई मौतों में सप्ताह में लगभग 37 फीसद वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि 16 राज्यों के 70 जिलों में पिछले 15 दिनों में कोरोना मामलों में 150 फीसद की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 1 फीसद से कम है। हालांकि, यह 0.4 फीसद से बढ़कर 0.6 फीसद हो गई है।पंजाब की पॉजिटिविटी रेट दर अब 6.8 फीसद है, यह चिंताजनक है। इससे पता चलता है कि कोरोना को लेकर उचित व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि भारत का कोविड वैक्सीन अपव्यय का कुल प्रतिशत 6.5 फीसद है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रमशः 17.6 फीसद और 11.6 फीसद वैक्सीन अपव्यय दर्ज किया गया।

इस बारे में हमने राज्यों से कहा है कि टीका अपव्यय को काफी कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने राज्यों से कुशल तरीके से इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इस पर रोक लगाने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज करना होगा।

सुवेंदु अधिकारी का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी के मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पार्टी का दावा है कि शुवेंदु ने वोटर कार्ड में गलत पता दर्ज कराया है। भाजपा में शामिल हुए सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से टीएमसी प्रमुख ममता को चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नंदीग्राम से अपना वोटर कार्ड भी बनवाया है। 12 मार्च को सुवेंदु ने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल किया था। इसी दिन उनका नया वोटर कार्ड भी सामने आया था। जिसमें नंदनायकबाड़, नंदीग्राम नया पता दिखाया गया है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री व नंदीग्राम सीट से चुनावी प्रतिद्वंद्वी ममता बनर्जी पर अपने हलफनामे में छह आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उनकी उम्मीदवारी रद करने की मांग की थी।

सुवेंदु ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने हलफनामे में असम में उनके खिलाफ दर्ज पांच मामलों और बंगाल में सीबीआइ द्वारा दर्ज एक मामले के बारे में सूचना छिपाई है। सुवेंदु ने उन केस नंबरों का भी उल्लेख किया है, हालांकि ममता ने क्या-क्या अपराध किए हैं, इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया है।

मुंबई पुलिस कमिश्नर होंगे हेमंत नगराले

मुंबई, (एजेंसी)। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें अब डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह पर हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

गृहमंत्री अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह के ट्रांसफर के बारे में जानकारी दी है। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में एनआईए की ओर से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मनसुख हिरानी की हत्या हुई।

प. बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा, हर साल पांच लाख को देंगे रोजगार

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस का मेनिफेस्टो जारी कर दिया। ममता को पहले 11 मार्च को पार्टी का मेनिफेस्टो जारी करना था, लेकिन 10 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करने के दौरान चोट लगने की वजह से उन्हें यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ गया था। इसके बाद पार्टी ने बुधवार को मेनिफेस्टो जारी कर दिया।

मेनिफेस्टो जारी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम बेरोजगारी कम करेंगे। एक साल में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ममता ने कहा कि जब टीएमसी सत्ता में आई तो हमारा राजस्व लगभग 25,000 करोड़ रुपए था, अब यह 75,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे पहले, झारग्राम जिले के गोपीबल्लवपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उन पर शारीरिक हमला किया करती थी और अब बीजेपी भी वही कर रही है।

आधार से लिंक न होने के कारण राशन कार्ड कैंसिल होने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने देश में करीब तीन करोड़ राशन कार्ड निरस्त किए जाने को गंभीर मामला बताया है। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों से जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण करीब तीन करोड़ राशन कार्ड रद किया गया है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एसी बोपन्ना व जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की बेंच ने बुधवार को कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मामले पर अंतिम सुनवाई होगी। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता कोयली देवी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि याचिका एक बड़े मामले को उठाती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बंबई हाईकोर्ट में भी मेरे सामने इसी प्रकार का मामला आया था। मुझे लगता है कि यह मामला संबंधित हाईकोर्ट में दायर किया जाना चाहिए था। इसके साथ ही बेंच ने वकील से कहा कि उन्होंने मामले का दायरा बढ़ा दिया है।

सुनवाई के दौरान गोंजाल्विस ने दलील दी कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि केंद्र ने करीब तीन करोड़ राशन कार्ड रद कर दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह किसी अन्य दिन मामले की सुनवाई करेगी क्योंकि गोंसाल्वेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड रद कर दिए हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि गोंसाल्वेस ने यह गलत बयान दिया कि केंद्र ने राशन कार्ड रद कर दिए हैं। इस पर बेंच ने कहा कि हम आपसे (केंद्र से) आधार कार्ड मामले के कारण जवाब मांग रहे हैं। यह विरोधात्मक मुकदमा नहीं है।हम अंततः इस पर सुनवाई करेंगे। नोटिस जारी किए जाए, जिन पर चार सप्ताह में जवाब दिया जाए।

यह याचिका कोयली देवी ने दायर की है, जिसकी झारखंड में 11 साल की बेटी संतोषी की भूखे रहने के कारण 28 सितंबर, 2018 को मौत हो गई थी। संतोषी की बहन गुड़िया देवी मामले में संयुक्त याचिकाकर्ता है। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकारियों ने उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण रद कर दिया था, जिसके कारण उनके परिवार को मार्च 2007 से राशन मिलना बंद हो गया था और पूरा परिवार को भूखे रहने पर मजबूर होना था और उनकी बेटी संतोषी की भोजन नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गई।

नई दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत करते हुए।

भारत में अब तक 3.64 करोड़ से अधिक कोरोना टीके की खुराक दी गई: सरकार

नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि अबतक देश में कोविड-19 टीके की कुल 3.64 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक बुधवार शाम सात बजे तक कोविड-19 टीके की 3,64,67,744 खुराक दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 75,47,958 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। स्वास्थ्य कमर्मियों में 46,08,397 को दूसरी खुराक भी लग चुकी है। इसके अलावा 76,63,647 अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों को टीका लगाया गया है जिनमें से 17,86,712 कर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं।

इनके अलावा 60 साल से अधिक उम्र के 1,24,74,362 लाभार्थियों को और 45 से 60 साल उम्र के गंभीर बीमारी से जूझ रहे 23,86,568 लोगों को भी कोविड-19 का टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, %%देश व्यापी टीकाकरण अभियान के 60वें दिन (बुधवार को) शाम सात बजे तक टीके की 14,03,208 खुराक दी गई। मंत्रालय ने बताया, %% इनमें से 12,10,498 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई जबकि 1,92,710 स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यकत कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई।

मंत्रालय के मुताबिक अंतिम रिपोर्ट देर रात तक आएगी। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को जिन को 12,10,498 लोगों को पहली खुराक दी गई, उनमें से 8,84,918 की उम्र 60 साल से अधिक थी जबकि 2,60,160 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच थी और वे अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। गौरतलब है कि 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ देशव्यापी टीकाकरण की शुरुआत हुई। दो फरवरी से अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों का भी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इसके अगले चरण में एक मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ।

स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में दावा: मुश्किल हालात में भी युवाओं से ज्यादा खुश और पॉजिटिव रहे बुजुर्ग, वजह- सिर्फ पैसों के लिए काम की बाध्यता नहीं रही

वाशिंगटन। अमेरिका में कोरोना महामारी से बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यहां अब तक साढ़े 5 लाख लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें 50 साल से अधिक उम्र के 51त्न लोग शामिल हैं। सुखद यह है कि जवानों की तुलना में बुजुर्ग कहीं ज्यादा खुश और सकारात्मक रहे हैं। इसका खुलासा स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में हुआ है। रिसर्च के मुताबिक, ढलती उम्र के साथ चुनौतियों से निपटने और मुश्किल हालात में सामंजस्य बिठाने की क्षमता बढ़ जाती है। कोरोनाकाल में उन्हें इसका फायदा भी मिला है।

सकारात्मक भावों का स्तर अधिक रहा

रिसर्च टीम का नेतृत्व करने वालीं स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीर्घायु केंद्र की मनोविज्ञानी लॉरा कार्स्टेंसन का कहना है कि बूढ़े होने के साथ लोगों में भले ही मानसिक तीव्रता का स्तर घटता है या शारीरिक कमजोरी आती हो, लेकिन उनकी खुशी में इजाफा होता है। युवाओं की तुलना में 50 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में सकारात्मक भावों का स्तर अधिक रहता है। वे बहुत कम नकारात्मकता महसूस करते हैं। इस उम्र के लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करने और क्रूर बॉस या मकान मालिक को बर्दाश्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस अवस्था में वह बहुत लंबे समय की तुलना में रोजमर्रा की गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जो निःस्वार्थ आनंद देता है। दादा-दादी बनने के बाद बच्चों की देखरेख, स्कूल लाने-ले जाने जैसे कामों में व्यस्त रहने के कारण उनके जीवन में तनाव नगण्य हो जाता है।

कोरोना से बुजुर्गों का जीवन ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ

इस उम्र में अक्सर लोग भविष्य में क्या बन सकते हैं, इसकी तुलना में वर्तमान में वे क्या हैं, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। यही वजह है जो उन्हें युवकों की तुलना में ज्यादा खुश रखती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक सुजैन चार्ल्स का कहना है कि जब महामारी फैल रही थी तो सभी ने यह माना कि बुजुर्गों पर इसका ज्यादा असर हो रहा है। युवाओं की तुलना में वे ज्यादा जान गंवा रहे थे। लेकिन इन शोधों के बाद अब बुजुर्ग कह सकते हैं कि उनका जीवन इतना प्रभावित नहीं हुआ, जितना उनके बच्चों या नाती-पोतों का हुआ है।

कोरोना दुनिया में: जर्मनी, फ्रांस और इटली ने भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल रोका, कंपनी ने कहा- हमारा टीका सुरक्षित

जर्मनी। यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस और इटली ने सोमवार को एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसकी वजह वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आना है। सबसे पहले नॉर्वे में ऐसे केस मिले थे। इसके बाद आयरलैंड और नीदरलैंड्स ने रविवार को इस टीके पर अस्थाई रोक लगा दी थी। आयरलैंड के डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. रोनन ग्लिन ने कहा कि नॉर्वे की मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग के 4 मामले सामने आए, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। वहीं, नीदरलैंड्स की सरकार ने कहा कि वैक्सीन पर यह सस्पेंशन कम से कम 29 मार्च तक जारी रहेगा। हालांकि, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित कई पब्लिक हेल्थ एजेंसियों का कहना है कि लाखों लोगों को बिना ऐसी समस्या के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक्सपर्ट्स भी वैक्सीन और और ब्लड क्लॉटिंग के बीच संबंध नहीं तलाश पाए हैं। इस बीच कंपनी ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। इस तरह की खबरें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के लिए झटका है। इस वैक्सीन के बारे में पहले से यह धारणा बन चुकी है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इसने बाकी वैक्सीन के मुकाबले कम एफिकेसी दिखाई है।

हालांकि, बड़े पैमाने पर जुटाया गया डेटा दिखाता है कि यह वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। खास तौर पर गंभीर बीमारी के मामलों में मौत की आशंका को कम करती है। दुनिया के कई देशों में सिर्फ एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही उपलब्ध है। यूरोपीय की मेडिसिन एजेंसी और दूसरी रेगुलेटरी इस बात की जांच कर रहे हैं कि वैक्सीन और खून के थक्के जमने के बीच लिंक के सबूत है या नहीं। एस्ट्राजेनेका ने रविवार को अपने प्रोडक्ट का बचाव करते हुए कहा कि कंपनी लगातार इसकी सेफ्टी की मॉनिटरिंग कर रही है। कंपनी के चीफ मेडिकल ऑफिसर एन टेलर ने कहा कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन में लगभग 1.7 करोड़ लोगों को हमारी वैक्सीन लगाई गई है। उनके डेटा का रिव्यू किया गया है। इसमें वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को कहा कि मेडिसिन एजेंसी की रिपोर्ट आने तक वैक्सीन का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास से बौखलाई किम जोंग की बहन ने बाइडन प्रशासन को दे डाली ये धमकी

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन पर पहली बार निशाना साधते हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास की निंदा की है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को आगाह किया कि यदि अगले चार साल तक रात में उन्हें आराम की नींद लेनी है तो उकसावे जैसा कोई काम न करें। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन व रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस सप्ताह दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। स्थानीय न्यूज एजेंसी के अनुसार किम की बहन ने सियोल के साथ सैन्य शांति समझौते को तोड़ने की धमकी दे डाली। उनकी यह बौखलाहट अमेरिका व दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे सैन्य अभ्यास को लेकर है। अमेरिका के दोनों वरिष्ठ मंत्री उत्तर कोरिया और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर जापान और दक्षिण कोरिया से बात करने के लिए एशिया गए हैं, जिसके बाद ये सियोल में अधिकारियों से मिलेंगे।

नेपाल में प्रचंड की कवायद

पुष्प कमल ने पार्टी के नाम से माओवाद शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा, कहा- जो माओ को पसंद नहीं करते उन्हें साथ लाएंगे

यंगून। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपनी पार्टी के नाम के आगे से माओवादी सेंटर हटाने का प्रस्ताव रखा है। इस कवायद के पीछे प्रचंड का तर्क है कि कम्युनिस्ट विचारधारा वाले ऐसे लोग, जो माओ को पसंद नहीं करते हैं, उन सभी को साथ लाएंगे। पार्टी के शिवकुमार मंडल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड हमेशा से कम्युनिस्टों की एकता के हामी रहे हैं। इसलिए उन्होंने अब पार्टी के नाम के आगे से माओ शब्द हटाने का प्रस्ताव किया है। अब कम्युनिस्टों को एक करने में उनके प्रयासों को तेज किया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी की मान्यता रद्द की: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली सीपीएन (यूएमएल) और पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी सेंटर) के विलय की मान्यता को रद्द कर चुका है। दोनों ने 2018 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) बनाई थी। नेपाल के चुनाव आयोग ने मंगलवार को ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन (यूएमएल) और प्रचंड की अगुवाई में सीपीएन (माओवादी सेंटर) से पूछा कि अगर वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी पार्टियों का फिर से विलय करने का फैसला करते हैं, तो वे पार्टी का नया नाम और चुनाव चिन्ह लेकर आएं।

प्रचंड ने अपने मंत्रियों को इस्तीफा देने को कहा

इससे पहले नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी सेंटर) के प्रमुख पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने रविवार को दूसरी बार ओली की अगुवाई वाली सरकार से अपने मंत्रियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। शनिवार को भी प्रचंड गुट ने अपने सभी मंत्रियों को अगले 24 घंटे में अपना रुख साफ करने को कहा था। इनमें गृहमंत्री राम बहादुर थापा, ऊर्जा मंत्री, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री बहादुर रायामाझी, जल आपूर्ति मंत्री मणिचंद्र थापा, शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह, खेल और युवा मामलों के मंत्री दावा लामा तमांग और श्रम मंत्री गौरीशंकर चौधरी शामिल हैं।

प्रचंड गुट को पार्टी में टूट का डर

प्रचंड गुट ने अब तक दो बार अपने मंत्रियों को इस्तीफा देने का निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे में मंत्रियों का रुख कहीं न कहीं पार्टी विरोधी लग रहा है। प्रचंड की पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य गणेश शाह ने कहा कि ओली सरकार में हमारे मंत्री इस्तीफा देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। पार्टी अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से लिखेगी। ओली ने शुक्रवार को केंद्रीय समिति की बैठक की थी, जिसमें 23 नेताओं को समिति में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया था। इसे प्रचंड ने अपनी पार्टी तोड़ने की साजिश बताते हुए ओली पर हमला किया था।

अपने मंत्रियों पर कार्रवाई कर सकते हैं प्रचंड

पार्टी नेताओं के अनुसार, रविवार की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी चर्चा हुई। उद्योग मंत्री लेखराज भट्टा, शहरी विकास मंत्री प्रभु साह और श्रम मंत्री गौरीशंकर चौधरी सीपीएन (एमसी) से संबंधित सांसद हैं, जबकि जल आपूर्ति मंत्री मणि थापा और युवा मंत्री दावा लामा पार्टी के केंद्रीय नेता हैं। ऐसे में अगर वे पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो उन्हें दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री का भारत दौरा

अप्रैल के आखिरी में भारत आएंगे बोरिस जॉनसन

यूके के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद यह उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में भारत दौरे पर आएंगे। उनके ऑफिस के हवाले से न्यूज एजेंसी रायटार्स ने बताया कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद बोरिस की यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी।

चीन को घेरने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भारत के साथ मिलकर चीन की आक्रामक हरकतों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर भी चर्चा कर सकते हैं। ब्रिटेन और चीन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, इनमें हांगकांग, कोरोना और

हुआवेई को ब्रिटेन के 5जी नेटवर्क में सक्रिय भूमिका से दूर रखना प्रमुख हैं। वहीं, क्वीन एलिजाबेथ को वॉरशिप की तैनाती से दक्षिण चीन सागर में सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका है। चीन इस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाना चाहता है।

बोरिस ने भारत आने का किया था वादा

इससे पहले गणतंत्र दिवस पर भारत को शुभकामनाएं देते हुए बोरिस ने कहा था कि मैं इस साल भारत आने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारी दोस्ती को मजबूत कर सकें, रिश्तों को आगे बढ़ा सकें। मैं जून में होने वाली फीसदी7 समिट से पहले ही भारत आऊंगा।

फीसदी7 के लिए मोदी को न्यौता भेजा

प्रधानमंत्री मोदी जून में ब्रिटेन जाएंगे। यहां वे फीसदी7 समिट में हिस्सा लेंगे। कॉर्नवाल में होने वाली समिट के लिए मोदी को ब्रिटेन ने न्यौता भेजा था। फीसदी7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं।

भारत ने कहा- उपदेश देना बंद करे और जातीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये पर ध्यान दे पाक

जिनेवा। भारत ने सोमवार को कहा, अब समय आ गया है कि एक 'नाकाम देश' पाकिस्तान को उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकार्ड और जातीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति उसके भेदभावपूर्ण रवैये पर तत्काल ध्यान दे। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान उपदेश देना बंद करे और अपने यहां लाखों पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दे। मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि के वक्तव्य के बाद अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने यह बात कही। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव फ्वन कुमार बाधे ने कहा, 'परिषद को पाकिस्तान के जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण बर्ताव एवं उसके निंदनीय मानवाधिकार रिकार्ड पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। अब समय आ गया है कि एक विफल देश पाकिस्तान उपदेश देना बंद करे और अपने यहां के लाखों पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दे।' संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर एक बार फिर व्यापक सुधार की मांग जोर पकड़ रही है और चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने की मांग उठ रही है। इस वैश्विक मंच की मौजूदा चुनौतियों पर बात करने से पहले इसके इतिहास पर नजर डालना समीचीन होगा। द्वितीय विश्वयुद्ध का विध्वंसक रूप देखने के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने तथा शांति की स्थापना के लिए 24 अक्तूबर, 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इससे पहले लीग ऑफ नेशन्स का गठन किया गया था, जो कुछ वजहों से वह अप्रभावी हो गया।

140 साल का सबसे बर्फीला तूफान

48 घंटे में 5 फीट तक बर्फ गिरी; 2400 उड़ानें रद्द, बर्फीला तूफान से 35 लाख लोग प्रभावित

डेनवर। अमेरिका में एक महीने में दूसरी बार बर्फीले तूफान ने दस्तक दी। जिसने पिछले 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोलोराडो, व्योमिंग और नेब्रास्का समेत 6 राज्यों में 48 घंटे में 5 फीट तक बर्फ गिरी। इससे 80 से ज्यादा हाईवे बंद हो गए। दो दिन में 2400 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। साथ ही करीब 35 लाख लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, आमतौर पर अमेरिका में मार्च में बर्फबारी नहीं होती। इस दौरान यहां का तामपान 10 से 15 डिग्री के बीच होता है। लेकिन साइबेरिया की तरफ से चली ठंडी हवाओं के कारण बर्फबारी हुई। तापमान माइनस 11 डिग्री तक पहुंच गया। इससे पहले मार्च, 1881 में 24 इंच बर्फबारी हुई थी।

बिजली-पानी का संकट बन गया था बर्फीला तूफान

पिछले माह आर्कटिक ब्लास्ट के कारण अमेरिका में 122 साल का सबसे बर्फीला तूफान आया था। इस कारण टेक्सास समेत 12 राज्यों में भारी बर्फ गिरी थी। तूफान की चपेट में आकर 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे।ली 3त्न, स्पेन 3त्न और ब्रिटेन 2फीसदी DST वसूलता है।

अपराध से परेशान महिलाओं का सब्र टूटा

ऑस्ट्रेलिया के 40 शहरों में असमानता और यौन हिंसा के खिलाफ मोर्चा खोला; 85 हजार महिलाओं ने मार्च फॉर जस्टिस निकाला

मैक्सिको। मैक्सिको में महिला दिवस पर अपराध से त्रस्त महिलाओं का सब्र टूटा। उन्होंने यौन उत्पीड़न के राष्ट्रपति आवास के पास इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस से भिड़ गईं। फिर 7 दिन बाद ही ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक महिला की हत्या के खिलाफ महिलाओं ने अपराध के खिलाफ मोर्चा खोला। अब यह विरोध की आग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है।

महिलाओं से अन्याय, लैंगिक असमानता, कार्यस्थल में उनके साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार खत्म करने की मांग को लेकर राजधानी कैनबरा समेत 40 अन्य शहरों में प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन दुष्कर्म के दो आरोपों के बाद उठे विवाद की पृष्ठभूमि में हुए हैं। प्रदर्शन के लिए मुख्य शहरों में जुटीं हजारों महिलाओं ने मार्च फॉर जस्टिस निकाला। मार्च के आयोजकों का दावा है कि रैलियों में करीब 85,000 महिलाएं शामिल हुईं। सरकार के खिलाफ गुस्सा जताते हुए आयोजकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीएम स्कॉट मॉरिसन से मिलने का प्रस्ताव तक ठुकरा दिया।

आयोजकों के प्रवक्ता जेनिन हेंड्री ने संसद भवन के बाहर कहा, 'हम उनके कार्यालय से 200 मीटर दूर हैं। हमारा बंद दरवाजों के पीछे मिलना उचित नहीं है। हम पहले ही आपके दरवाजे पर आ गए हैं, अब सरकार को देखना है कि वह चौखट लांघकर हमारे पास आए। हाल ही में दुष्कर्म के दो मामले सामने आए हैं। एक में अटॉर्नी जनरल क्रिश्चियन पोर्टर पर आरोप लगा है। दूसरा संसद भवन में महिला कर्मचारी से कथित दुष्कर्म का है।

काले कपड़ों में विरोध, पीड़िताओं की सूची बिछाई

मेलबर्न में बीते 4 साल में जुर्म का शिकार हुई महिलाओं का नाम लिखा कपड़ा बिछाकर प्रदर्शन किया गया। राजधानी कैनबरा में संसद भवन के सामने सैकड़ों लोगों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। उन पर लिखा था- 'महिलाओं को न्याय दो' और 'पुरुष अपराध स्वीकारें।' महिलाओं काले कपड़े में विरोध कर रही थीं।

कोरोना दुनिया में: मार्च के 15 दिनों में 61 लाख से ज्यादा केस सामने आए; स्पेन-पुर्तगाल ने भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगाई

काठमांडू। दुनियाभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च के शुरुआती 15 दिनों में ही 61 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें भी 7 दिन तो रोजाना मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख से भी ज्यादा था। वहीं, 12 मार्च को सबसे ज्यादा 4.90 लाख कोरोना संक्रमित मिले थे। इन 15 दिनों में अब तक 61 लाख 4 हजार 599 संक्रमित मिले, जबकि एक लाख 27 हजार 43 लोगों की मौत भी हुई।

उधर, एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन पर रोक का सिलसिला देश-दर-देश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को स्पेन और पुर्तगाल ने भी इस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। इन देशों में यह वैक्सीनेशन लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत मिली थीं।

यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी रिपोर्ट सौंपेगी

इससे पहले सोमवार को जर्मनी, फ्रांस और इटली ने वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी थी। आयरलैंड और नीदरलैंड्स ने रविवार को इस टीके पर अस्थाई रोक लगा दी थी। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि उनके देश में भी एहतियातन मंगलवार तक के लिए वैक्सीन पर पाबंदी लगाई गई है। इसी दिन यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी वैक्सीन पर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि फ्रांस को उम्मीद है कि जल्द ही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फिर से लोगों को दी जाएगी।

इन देशों में भी रोक

डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, लातविया और गैर-यूरोपीय संघ के देश नॉर्वे और आइसलैंड ने भी ब्लड क्लॉटिंग की रिपोर्टों के बाद एहतियातन वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

कंपनी का दावा- वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित

यूरोपीय की मेडिसिन एजेंसी और दूसरी रेगुलेटरी इस बात की जांच कर रहे हैं कि वैक्सीन और खून के थक्के जमने के बीच लिंक के सबूत है या नहीं। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन का बचाव करते हुए दावा किया कि कंपनी लगातार इसकी सेफ्टी की मॉनिटरिंग कर रही है और अब तक यह पूरी तरह सुरक्षित पाई गई है।

> दुनियाभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च के शुरुआती 15 दिनों में ही 61 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

कंपनी के चीफ मेडिकल ऑफिसर एन टेलर ने कहा कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन में लगभग 1.7 करोड़ लोगों को हमारी वैक्सीन लगाई गई है। उनके डेटा का रिव्यू किया गया है। इसमें वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं।

दुनिया में 12.07 करोड़ मरीज

दुनिया में कुल मरीजों की संख्या 12 करोड़ के पार पहुंच गई है। अभी यह आंकड़ा 12.07 करोड़ से ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 3.36 लाख नए संक्रमित मिले हैं। 6 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। अब तक 9 करोड़ 73 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। 26 लाख 71 हजार से ज्यादा ने जान गंवाई है। दुनियाभर में फिलहाल 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

जनता की शक्तियों को उपराज्यपाल को देने के खेल में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनो शामिल है: चौ. अनिल कुमार

नई दिल्ली(वेबवार्ता)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चै. अनिल कुमार के नेतृत्व में भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा संसद में जीएनसीटी दिल्ली 1991 एक्ट में संशोधन करके दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों को उपराज्यपाल के हाथों में सौंपने के कदम के विरोध में आज हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर धरना दिया गया। इस एक्ट में संशोधन करके भाजपा जनता की जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध सरकार को सभी शक्तियों और कार्यपालिका के निर्णयों के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी आवश्यक होगी। एक्ट में संशोधन करके दिल्ली की जनता के अधिकार विहीन बनाने का काम भाजपा के अमित शाह और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल दोनो ने मिलकर किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा मोदी सरकार का एक्ट में संशोधन के खिलाफ विरोध करना मात्र ढोंग है। चै. अनिल कुमार ने कहा कि एक्ट में बदलाव दिल्ली की जनता के अधिकारां और भावनाओं पर कुठाराघात है, कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी संशोधन बिल की सच्चाई को पूरी दिल्ली के सभी वार्डों तक पहुँचाकर दिल्लीवासियों के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक लड़ेगी। चै. अनिल कुमार ने कहा कि इस बिल पर जनता की जवाबदेही के रुप में अरविन्द केजरीवाल की भूमिका संदेह के घेरे में है और जनता भविष्य में उन्हें इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जब 3 फरवरी, 2021 को जीएनसीटी दिल्ली 1991 एक्ट संशोधन की केबिनेट की मंजूरी मिल गई, तब से 16 मार्च, 2021 तक अरविन्द सरकार ने दिल्लीवासियों के हितों के लिए आवाज क्यों नही उठाई और शायद उन्होंने इस बिल के विरोध में प्रधानमंत्री अथवा गृहमंत्री से मिलने का समय इसलिए नही मांगा, क्योंकि वह बिल को लागू करने में केन्द्र सरकार के सहयोगी के रुप में काम कर रहे थे। यही कारण था कि केजरीवाल सहित पूरी केबिनेट और 62 विधायको ने 45 दिनों तक कोई भी विरोध जाहिर नही किया और आज जब कांग्रेस जीएनसीटी दिल्ली 1991 एक्ट संशोधन का विरोध जंतर मंतर पर कर रही है तो केजरीवाल भी जनता की सहानूभूति लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके जब जम्मू कश्मीर और लद्याख को जब केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा था तब अरविन्द केजरीवाल संसद में उस बिल का समर्थन कर रहे थे, और घड़ियाली आंसू बहा रहे है। धरने में चै. अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने जीएनसीटी दिल्ली 1991 एक्ट संशोधन से साफ कर दिया है कि दिल्ली का सरकार का मलतब उपराज्यपाल है। चै. अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली को 1993 से पूर्ण

एक्ट में संशोधन करके दिल्ली की जनता के अधिकार विहीन बनाने का काम भाजपा के अमित शाह और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल दोनो ने मिलकर किया है।

राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करने वाली भाजपा प्रत्येक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात करती है और आंदोलन के द्वारा सत्ता में आए अरविन्द केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली की जनता से चुनावी वायदा किया था कि सत्ता में आने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाऐंगे, परंतु आज अरविन्द केजरीवाल भाजपा की बी-टीम के रुप में अपनी सरकार को कठपुतली के रुप में काम कर रहे है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना तो दूर, जो अधिकार दिल्ली को मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। चै. अनिल कुमार ने कहा कि मोदी सरकार के तानाशाह शासन में जनविरोधी नीति व योजनाओं के कारण सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का जनमानस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का कथन बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता दिखाई देता है क्योंकि पिछले 6 वर्षों में मोदी-अमित शाह ने अपने नजदीकियों को फायदा पहुचाने के लिए जहां सत्ता में आते नोटबंदी और जीएसटी को लागू करके देश में आर्थिक मंदी का दौर ला दिया, वही फायदे पहुचाने वाली सरकारी कम्पनियों, एयरपोर्ट, कृषि क्षेत्र में निजीकरण के लिए तीन काले कानून बनाना देश की आर्थिक व्यवस्था ढ़ह गई और अब बैंकों का नीजिकरण करके अर्थव्यवस्था की नींव पूरी तरह खोखली करनी का प्रारुप तैयार कर दिया है।

नाक से नीचे हुआ मास्क तो यात्रियों को फ्लाइट से उतरना पड़ेगा

सख्त हुए नियम, डीजीसीए ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। देशभर में एक बार फिर से तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हवाई यात्रा के दौरान मास्क नहीं पहनना अब आपको भारी पड़ सकता है। यूं कहें तो आप यात्रा से भी वंचित होने के साथ-साथ अनियंत्रित यात्री का तगमा अलग दिया जाएगा। जी हां, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि चेतवानी दिए जाने के बाद भी सही से मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जस्टिस नवीन चावला और सी. हरि.शंकर की बेंच के समक्ष डीजीसीए ने यह भी कहा कि चेतावनी के बाद भी सही से मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को उड़ान भरने से पहले विमान से उतार दिया जाएगा, यानी उन्हें यात्रा नहीं करने दी जाएगी। डीजीसीए ने बेंच को बताया कि ऐसे यात्रियों को अनरूली पैसेंसजर यानी अनियंत्रित यात्री माना जाएगा। बेंच ने डीजीसीए द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर संतोष जताते हुए कहा कि उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण से यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसी भावना और लगन से कार्रवाई जारी रहेगी। बेंच ने कहा कि पहले वह स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए इस मामले को आगे भी जारी रखने के पक्ष में थे ताकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिशा-निर्देशों के पालन की निगरानी हो सके। बेंच ने कहा कि हालांकि डीजीसीए द्वारा सक्रियता से उठाए जा रहे कदमों के मद्देनजर वह (अदालत) अब इस मामले को बंद करने का फैसला किया। बेंच ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करना

एक स्वागत योग्य कदम है। जस्टिस हरि.शंकर ने 8 मार्च को हवाई अड्डे से विमान तक जाने के दौरान ठीक से मास्क नहीं पहनने और यात्रियों द्वारा मास्क नहीं पहनने के लिए उनकी जिद्दी अनिच्छा को लेकर संज्ञान लिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीसीए और अन्य सभी एयरलाइनों को तत्काल कोरोसा संक्रमण से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। जस्टिस हरि. शंकर ने 5 मार्च को कोलकाता से दिल्ली हवाई यात्रा के दौरान खुद इस बात का अनुभव किया था कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या ठीक से नहीं पहन रहे हैं। डीजीसीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बेंच को बताया कि 13 मार्च को सर्कुलर जारी किया गया है। शर्मा ने बेंच को बताया कि इसके तहत विमान में, यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बाद भी ठीक से मास्क पहनने के निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसे प्रस्थान से पहले जरूरत पड़ने पर डी-बोर्ड किया जाना चाहिए यानी विमान से उतार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विमान में यदि बार-बार निर्देश के बाद भी मास्क पहनने से इनकार करता है या बार-बार चेतावनी के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो ऐसे यात्री को अनियंत्रित यात्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

पद्मश्री वीरेंद्र प्रभाकर के नाम पर सड़क का नामकरण किया

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। उत्तरी दिल्ली निगम द्वारा पद्मश्री वीरेंद्र प्रभाकर के नाम पर पुरानी दिल्ली में एक सड़क का नामकरण किया गया। म?हापौर जयप्रकाश ने बुधवार को एक समारोह में वार्ड नंबर 88 एन में आसफ अली रोड से कमला मार्केट और पंजाबी मार्केट के बीच से होते हुए जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर मिलने वाली सड़क का नामकरण किया। इस दौरान विधायक शुएब इकबाल, नगर निगम में कांग्रेस पार्षद के नेता मुकेश गोयल, पार्षद आले इकबाल, नगर निगम में स्थाई समिति के उपाध्यक्ष रहे अशोक जैन आदि मौजूद थे। इस दौरान महापौर जयप्रकाश ने कहा कि पद्मश्री वीरेंद्र प्रभाकर विख्यात फोटो पत्रकार थे। उन्होंने महात्मा गांधी के छोटे पुत्र देवदास के साथ काम किया था।

निर्मल जैन ने कबाड़ से तैयार मोबाइल चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। निर्मल जैन ने आज पटपड़गंज स्थित निगम मुख्यालय में मोबाइल चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप-महापौर, हरि प्रकाश बहादुर, स्थायी समिति अध्यक्ष, सतपाल सिंह, नेता सदन, प्रवेश शर्मा, उद्यान समिति की अध्यक्ष, सुश्री नीतू त्रिपाठी, पर्यावरण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, वीर सिंह पंवार, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष, संदीप कपूर, वरिष्ठ पार्षदगण- सुश्री अपर्णा गोयल, सुश्री शशि चांदना और निगम अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा बेकार पड़े उपकरणों से मोबाइल चिल्ड्रेन पार्क तैयार किया गया है। यह पार्क पुराने ट्रक पर बनाया गया है जिसपर निगम के स्टोर से पुराने समान जैसे ग्रिल, शेड, लोहे का सामान आदि का इस्तेमाल करके करीब 8 झूले लगाए गए है। यह एक

चलता फिरता पार्क है जिसे विशेषकर उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए बनाया गया है जिनके घर के आस पास पार्क उपलब्ध नहीं है। महापौर निर्मल जैन ने इस अनूठी पहल के लिए उद्यान विभाग की प्रशंसा की और कहा कि पूर्वी दिल्ली के बच्चों के लिए इस प्रकार के और पार्क भी बनाये जाएंगे। जैन ने कहा कि पूर्वी दिल्ली सघन आबादी वाला क्षेत्र है जहां कई इलाकों में बच्चों के पास खेलने की पर्याप्त जगह नहीं है। यह पार्क ऐसे बच्चों के लिए निगम की ओर से खूबसूरत उपहार जैसा है। उपमहापौर, हरि प्रकाश बहादुर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का यह पार्क बच्चों के पास घर-घर जाएगा। पार्क बच्चों के पास खुद ही पहुंच जाए तो इससे आनंददायक बात और क्या ही होगी। स्थायी समिति अध्यक्ष, सत्यपाल सिंह ने कहा कि विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम का फिट इंडिया अभियान के तहत एक रचनात्मक और सुंदर प्रयास है। इससे ना केवल कबाड़ को रिसाइकल किया गया बल्कि बच्चों को खेल का साधन भी दिया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन,श्री प्रवेश शर्मा ने बताया कि यह पार्क उन बच्चों के लिए एक सौगात है जिनके घर के आसपास पार्क नहीं है।

उन्होंने बताया कि इस पार्क को आकर्षक रूप दिया गया है जो बच्चों को जरूर पसंद आएगा। उद्यान समिति की अध्यक्ष, सुश्री नीतू त्रिपाठी ने कहा कि मोबाइल पार्क के बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से चारों और सेफ्टी ग्रिल्स भी लगाए गए हैं। उन्होंने इसे तैयार करने वाले माली व अन्य स्टाफ का धन्यवाद दिया।

एक किलों प्लास्टिक देकर ले जूट व कपड़े का थैला

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। जय प्रकाश ने आज दिल्ली गेट स्थित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महिला हाट में प्लास्टिक मुक्त बाजार अभियान 2021 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिटी सदर पहाड़गंज वार्ड समिति के अध्यक्ष, मोहम्मद सादिक, पार्षद, आले मोहम्मद, रवि कसान, राकेश कुमार, क्षेत्रीय उपायुक्त, सुश्री शशांका अला व निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान निगम प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों ने अपशिष्ट पदार्थों से उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का भी प्रदर्शन किया। महापौर ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त बाजार अभियान के अंतर्गत सदर पहाड़गंज क्षेत्र में आने वाले बाजारों में विभिन्न स्थानों पर कियोस्क बनाए गए है जहा नागरिक एक किलों प्लास्टिक देकर एक जूट व कपड़े का थैला ले सकते है। उन्होंने बताया कि इस अभियान से गलियों व लैंडफिल साइट पर प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद मिलेगी। महापौर जय प्रकाश ने कहा कि जिस प्रकार उत्तरी दिल्ली नगर निगम सीमित संसाधनों में नागरिकों को सेवाएं दे रही है, शहर का स्वच्छ रखने के लिए कार्य कर रही है और एकल प्रयोग प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रही है वो एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका सपना है एकल प्रयोग प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो उसके लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम विभिन्न माध्यमों से एकल प्रयोग प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चाल रही है ताकि नागरिकों को एकल प्रयोग प्लास्टिक के पर्यावरण पर बुरे असर के बारे में जागरूक किया जा सके। महापौर ने कहा कि हमें स्वयं भी प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए और दूसरों को भी एकल प्रयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से रोकेंगे चाहिए।

दि. न. नि की स्थाई समिति के अध्यक्ष राजदत गहलोत द्वारा पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने आज प्रथम तल सिविक सेंटर स्थित लाला हंसराज गुप्ता सभागार में पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन नरेन्द्र चावला ,पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सहरावत,चारों जोन के अध्यक्ष ,अतिरिक्त आयुक्त रमेश वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित हुए। बैठक में पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग के कार्यो कि समीक्षा करते हुए स्थाई समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने कहा कि पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग के कार्य जैसे साफ सफाई, नालों की साफ सफाई इत्यादि कार्य हर नागरिक को प्रभावित करते हैं तथा इसी विभाग के द्वारा किए कार्यों से निगम की छवि प्रभावित होती है। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए किए गए प्रयासों में सबसे ज्यादा योगदान इसी विभाग का है। पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग के कार्यों में सुधार हेतु उन्होंने सभी जोन के अध्यक्षों के सुझाव सुने तथा वहां उपस्थित अधिकारियों से उनके समाधान हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए। स्थाई समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने कहा कि दक्षिणी निगम के अधिकार क्षेत्र में बहुत सारी अनाधिकृत कालोनियां एवं जे. जे. कालोनियां है जहां पर तंग गलियां होने के कारण कूड़ा उठाने वाले ऑटो टिप्पर नही पहुंच पाते है।इसी समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने अधिकारियों को ट्रॉली एवं व्हील बेरो की उचित व्यवथा करने के आदेश दिए। गहलोत ने कहा कि निगम द्वारा संचालित शौचालयों में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रहे ताकि नागरिकों को इनके इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नेता सदन नरेन्द्र चावला ने डेम्स विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों की सफाई का कार्य सुचारू रूप से किया जाना चाहिए तथा नालों से निकली गाद का भी सही ढंग से प्रबंधन किया जाना चाहिए।

प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार के किए गए सराहनीय कार्यों की वजह से दिल्ली में 15 प्रतिशत कम प्रदूषण हुआ: गोपाल राय

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ किए गए सराहनीय कार्यों की वजह से दिल्ली में 15 प्रतिशत कम प्रदूषण हुआ है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली में 15 प्रतिशत प्रदूषण कम हुआ है, जबकि पहले दिल्ली दूसरे या तीसरे स्थान पर होती थी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में टॉप-10 की सूची में शामिल 9 शहरों में से अधिकतर उत्तर प्रदेश के शहर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदूषण के मसले पर गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद भी एनसीआर में चल रहे प्रदूषण पैदा करने वाले पावर प्लांट्स और ईंट भट्ठों को बंद नहीं किया गया। प्रदूषण के मसले पर संयुक्त प्रयास की जरूरत है। केंद्र सरकार को बंद हो चुके एयर क्वालिटी कमीशन को पुनः सक्रीय करना चाहिए, ताकि वह प्रदूषण पैदा करने वालों पर कार्रवाई कर सके। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें दो तथ्य

सामने आए हैं। एक यह कि भारत के अंदर टॉप-10 की सूची में जिन शहरों का नाम हैं, उनमें से 9 शहर वे हैं, जिसमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं। दिल्ली पहले ज्यादा प्रदूषित थी। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काफी सराहनीय कार्य किया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट ही बता रही है कि मौजूदा समय में दिल्ली के अंदर 15 प्रतिशत प्रदूषण कम हुआ है। पहले दिल्ली प्रदूषण के मामले में दूसरे या तीसरे स्थान पर होती थी, आज दिल्ली की स्थिति उससे काफी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम होने के पीछे कारण हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली अंदर ग्रीन बेल्ट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्रदूषित ईंधन पर जो भी उद्योग चल रहे हैं, हमने ऐसे उद्योगों को शून्य कर दिया है। उन सभी उद्योगों का ईंधन बदल दिया गया है। हम लोग दिल्ली के अंदर ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लेकर आए, दिल्ली के अंदर ईलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी लेकर आए, दिल्ली के अंदर धूल के प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाने की पॉलिसी लाए। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम करने का काम और तेज किया है। इसके लिए हमने वॉर रूम बनाया है। यह वॉर रूम 24 घंटे काम कर रहा है। इसके साथ ही हमने ग्रीन एप लांच किया है, जिससे प्रतिदिन प्रदूषण पर निगरानी की जा रही है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के साथ-साथ हम धूल के प्रदूषण को कम करने पर भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान चलाया।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रैंकिंग सुधारने के लिए तेज किए प्रयास

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। दक्षिणी निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021में रैंकिंग सुधारने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नागरिकों को खुले में शौच न करने के बारे में अवगत कराने के लिए पश्चिमी क्षेत्र ने अनूठी पहल की है। इस पहल के अंतर्गत आज पश्चिमी क्षेत्र के वार्ड नंबर 06 टैगोर गार्डन के ख्याला में स्कूटी एवं मोटरसाइकिल पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस पहल के बारे में बताते हुए पश्चिमी क्षेत्र के उपायुक्त राहुल सिंह ने बताया कि यह अपने प्रकार की पहली ऐसी रैली है जिसमे निगम के कर्मचारियों ने स्कूटी एवं मोटरसाइकिल के माध्यम से सम्पूर्ण क्षेत्र का चक्कर लगाया तथा नागरिकों को स्वछता संदेशों के माध्यम से खुले में शौच के दुषपभाव से अवगत कराया। इसी कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए पश्चिमी क्षेत्र के उपायुक्त राहुल सिंह ने बताया कि खुले में शौच की प्रवृति कई प्रकार की बीमारियों को दावत देती है, भूजल को प्रदूषित करती है तथा उस क्षेत्र को भी गंदा एवम प्रदूषित करती है जिसका सबसे बड़ा नुकसान वहां रहने वाली जनता को उठाना पड़ता है। इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बुरी आदत के विरुद्ध हमारा संदेश पहुंचाएंगे तथा भविष्य में हम ऐसे कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में आयोजित करेंगे। इसके अतिरिक्त दक्षिणी निगम ढ़लाव घरों, सामुदायिक शौचालयों, सड़कों की दीवारों आदि पर सुन्दर चित्रकारी से स्वच्छता के संदेश नागरिकों तक पहुँचा रहे हैं तथा विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रम, जागरूकता अभियान आदि भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के आयोजन से नागरिकों की सहभागिता बढ़ेगी और वे स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रति जागरूक होंगे तथा हमारे साथ जुड़ेंगे।

अंतिम चरण में काम चल रहा है अटल झील एवं उपवन का: मनोज तिवारी

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी अमृत योजना के तहत शाहदरा स्थित वेलकम में बनाए जा रहे पर्यटन स्थल भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेई झील एवं उपवन का कार्य अब अंतिम चरण में है जिसके बाद क्षेत्र को एक भव्य पर्यटन स्थल मिल जाएगा वही उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में विकास का एक और नया आयाम जुड़ेगा यह कहना है उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का गौरतलब है कि इस निर्माण कार्य का शुभारंभ केंद्र के जल शक्ति मंत्री पूर्वी दिल्ली के महापौर सहित सभी अधिकारियों के साथ सांसद मनोज तिवारी ने किया था लेकिन कोरोना महामारी के दौरान काम में रुकावट आने से विकास कार्य के पूर्ण होने में विलंब हुआ लेकिन अब तेजी से इस कार्य को पूरा किया जा रहा है मनोज तिवारी का कहना है कि अपनी तरह का यह दिल्ली का एकलौता पर्यटन स्थल होगा जिसमें बच्चों के खेलने का पार्क क्लब ओपन एयर जिम जैसी सुविधाएं होंगी वही एक साथ 800 लोग बैठ कर झील के सौंदर्यीकरण का स्वरूप देख सकेंगे ऐसा ओपन थिएटर भी बनाया जा रहा है झील में 4 सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं और 1फब्बारा सौंदर्य को और बढ़ाएगा बरसात के दौरान पानी को संरक्षित किया जाएगा वही परे वर्ष झील में पानी मौजूद रहे इसके लिए क्षेत्र के कई नालों के पानी को शोधित कर झील में भरा जाएगा जल शोधक संयंत्र से झील तक पानी को ले जाने के लिए घुमावदार एक नहर का निर्माण किया गया है जिसके किनारों पर घास फूल और पत्थरों से बनाए गए किनारों पर बैठकर आने वाले पर्यटक अद्भुत आनंद की अनुभूति करेंगे सब कुछ ठीक रहा तो आगामी 3 महीने में इस सारे विकास कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा पूरे निर्माण कार्य को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी बड़ी तत्परता से स्थानीय निगम पार्षद अजय शर्मा और विधायक जितेंद्र महाजन की देखरेख में कर रहे हैं।

संपति कर जमा ना कराने वालों पर निगम ने कसा शिकंजा, निगम ने 13 सपत्तियां की सील

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। पूर्वी दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी क्षेत्र द्वारा सम्पत्तिकर का भुगतान न करने वाले करदाताओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 13 सम्पत्तियों को निगम सील कर जा चुका है । निगम के अधिकारी आज जब श्रीराम कॉलोनी मे संपत्ति कर जमा न कराने पर सम्पत्तिधारक के भवन को सील करने पहुंचे तो भवन मालिक ने मौके पर 2,50,000/- का चेक निगम के खाते में दिया गया । निगम की माने तो अभी तक सील की गई सम्पत्तियों से 20,36,172/- प्राप्त हुए । पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्तिकर में ब्याज एवं जुर्माना 100 प्रतिशत की छूट देते हुए योजना लायी गयी है जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है । किन्तु सम्पत्ति स्वामी इसके बावजूद सम्पत्तिकर अदा करने में कोताही बरत रहे है । निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कॉलोनियों को प्रदान की जाने वाले नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में निगम को कठिनाई हो रही है । इसलिए खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए निगम ने कमर कस ली है और सम्पत्ति भुगतान न करने वाले के विरूद्ध 31 मार्च 2021 के बाद भी निगम द्वारा सख्त कार्यवाही करने का अभियान चलाया जाएगा । जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति को सील किया जाना भी शामिल हैं।

डीटीसी मुख्यालय पर कर्मचारियों ने जताया विरोध

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। डीटीसी कर्मियों ने अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को पक्का करने सहित अन्य मांगों को लेकर डीटीसी मुख्यालय पर बुधवार को प्रदर्शन किया। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान यातायात भत्ते का भुगतान करने, कर्मचारियों को कैशलेस से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रोन्नति में चालकों का कोटा बढ़ाने, अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को पक्का करने और सामान काम व सामान वेतन की मांग की। संघ के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने कहा कि डीटीसी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यालय के बाहर जुटे थे। डीटीसी प्रशासन से मांग है कि वह कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें। साथ ही डीटीसी बसों का बेड़ा बढ़ाकर उसे 11 हजार तक किया जाए। संघ के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन का आयोजन हुआ था।

इग्नू ने आवेदन की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। एमएलए प्रवासी छात्रों के लिए ऑनलाइन दाखिले के लिए आवेदन की तारीख इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने बढ़ा दी है। अब ये छात्र 31 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। सार्क, गैर-सार्क से प्रवासी छात्रों के लिए 16 ऑनलाइन पाठ्यक्रम, जिसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, स्नातक तथा परास्नातक कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू जनवरी 2021 सत्र (ओडीएल पाठ्यक्रम) के लिए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाता है। इसके अलावा इग्नू ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के आवेदन की तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। छात्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली में नेपाली महिला की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज से सुराग तलाश रही पुलिस

नई दिल्ली (वेबवार्ता)। राजधानी दिल्ली में बुधवार को दिनदहाड़े एक 45 वर्षीय नेपाली महिला की मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, यह घटना उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर इलाके के न्यू अरुणा नगर में सुबह 7 बजे के आसपास हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला की पहचान मीना के रूप में हुई है, जो इलाके में ही अपने पति के साथ नाश्ता और पेय पदार्थों की दुकान चलाती थी। महिला पिछले आठ साल से अपने पति और अपनी 12 साल की बेटी के साथ किराये के मकान में रह रही थी।

संपादकीय

हमें लॉकडाउन से आगे सोचना होगा

भारत में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। गुरुवार को देश भर में 23,285 नए मामले सामने आए, जो 23 दिसंबर, 2020 के बाद एक दिन में नए मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। इनमें से 60 फीसदी से अधिक (14,317 मामले) मरीज तो अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं, जबकि केरल में 2,133 और पंजाब में 1,305 नए मरीजों का पता चला। रोजाना के मामलों में नई बढ़ोतरी कर्नाटक (783), गुजरात (710) और तमिलनाडु (685) जैसे राज्यों में भी दिख रही है। इस तरह से देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1.97 लाख से ज्यादा हो गई है, जो कुल संक्रमित मरीजों का 1.74 प्रतिशत है। महाराष्ट्र को लेकर विशेष चिंता है। यहां 21 फरवरी को कोविड-19 मरीजों की संख्या 21 लाख को पार कर गई थी, पर 22 लाख के आंकड़े को छूने में इसे बमुश्किल 13 दिन लगे, जबकि 21 जनवरी को यह 20 लाख पर पहुंचा था। संक्रमण की इस बढ़ती रफ्तार के कारण ही नागपुर व अकोला जैसे इलाकों में लॉकडाउन लगाकर जनजीवन को रोक दिया गया है, और पुणे में रात्रिकालीन कर्फ्यू का एलान किया गया है। मुंबई में भी पॉजिटिविटी रेट (प्रति 100 जांच पर पॉजिटिव मामलों की दर) बढ़कर 7-7.5 फीसदी हो गई है और कहा गया है कि अगर यह दर 15 फीसदी के करीब पहुंच जाएगी, तो कई दूसरे प्रतिबंध आयद किए जाएंगे।

साफ है, संभलते हालात दोबारा से बिगड़ने लगे हैं। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि वायरस लगातार म्यूटेट (अपना चरित्र बदलना) कर रहा है। यह उसका नैसर्गिक गुण है। वह जितना अधिक फैलता है, उतना अधिक म्यूटेट करता है। अपने यहां हर महीने कम से कम दो बार वायरस अपना रूप बदल रहा है। चूंकि इसके संक्रमण को हम पूरी तरह से रोक नहीं पाए हैं, इसलिए इसका म्यूटेशन होता रहेगा। उल्लेखनीय है कि म्यूटेट वायरस फिर से पूरी आबादी के लिए खतरा बन जाता है। इससे संक्रमण का एक नया चरण आ सकता है। पिछली सदी के स्पेनिश फ्लू में हमने यह देखा था कि संक्रमण का दूसरा दौर जान-माल का भारी नुकसान दे गया।

दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमारे शरीर में इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई हो। छह-सात महीने में इसका खत्म होना स्वाभाविक है। हमारी तकरीबन 55-60 फीसदी आबादी इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर चुकी थी। चूंकि महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली जैसे राज्यों में शुरुआत में ही वायरस का प्रसार हो गया था, इसलिए बहुत मुमकिन है कि यहां 'हर्ड इम्यूनिटी' (करीब 60-70 फीसदी जनसंख्या में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाने की स्थिति) खत्म हो गई हो। नतीजतन, लोग फिर से संक्रमित होने लगे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए भी हैं, जिनमें एक बार कोरोना से ठीक हुआ मरीज दोबारा इसकी गिरफ्त में आ गया है। ऐसे में, फिर से सीरो सर्वे कराने की जरूरत आन पड़ी है। इसमें ब्लड सीरम की जांच करके यह पता लगाया जाता है कि कोई आबादी वायरस से किस हद तक लड़ चुकी है। अब तक तीन देशव्यापी सर्वे हो चुके हैं। भले ही हर सर्वे में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती दिखी, लेकिन जिस रफ्तार से इसके बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, वह हो नहीं सका। यह बताता है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी संभवतः खत्म हो रही है।

तीसरी वजह यह हो सकती है कि नए इलाकों में संक्रमण का प्रसार हो रहा होगा। महाराष्ट्र में अमरावती और नागपुर जैसे क्षेत्रों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि कभी धारावी जैसे इलाके कोविड-19 का केंद्र हुआ करते थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पूर्वी हिस्से की तुलना में मध्य दिल्ली और बाहरी सीमावर्ती इलाकों से अधिक मरीज मिलने के अनुमान हैं। इसका यह मतलब है कि जिन्हें पहले यह रोग नहीं हुआ है, उन पर खतरा कहीं ज्यादा है। हालांकि, संक्रमण की नई लहर नवजात शिशुओं की संख्या बढ़ने से भी आ सकती है, लेकिन कोरोना का नवजातों और बच्चों में अब तक कम असर दिखा है। मानवीय गतिविधियों के बढ़ने के कारण भी उछाल आए हो सकते हैं। भले ही अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की गई, लेकिन अब सारा आर्थिक जनजीवन पटरी पर लौट आया है। इस कारण बाजार में चहल-पहल बढ़ गई है। अच्छी बात यह है कि अपने यहां मृत्यु-दर अब भी कम है। यह 1.5 फीसदी के आसपास रुकी हुई है, जो संकेत है कि संक्रमण में यह उछाल जानलेवा नहीं है। यह हमारी बेहतर होती चिकित्सा व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवाओं का नतीजा है। बहरहाल, वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो अब लॉकडाउन से संक्रमण को थामना मुश्किल है। बेशक पिछले साल इसी उपाय पर हमारा पूरा जोर था, लेकिन इसका फायदा यह मिला कि कोरोना के खिलाफ हमने अपनी तैयारी चाक-चौबंद कर ली। अस्पतालों की सेहत सुधार ली। लेकिन अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सावधानी ही बचाव का सबसे जरूरी उपाय है। मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना और सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचना कहीं ज्यादा जरूरी है। हमें 'न्यू नॉर्मल' को अपनाना ही होगा। कोरोना संक्रमण के शुरुआती महीनों में इन पर ध्यान तो दिया गया था, लेकिन अब लापरवाही बरती जाने लगी है। यह काफी खतरनाक हो सकता है। कई लोग 'न्यू नॉर्मल' के नीरस होने का बहाना बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने यह धारणा बना ली है कि इसमें उन्हें घर में कैद होना पड़ेगा। ऐसा कतई नहीं है। मानसिक और सामाजिक सेहत के लिए हमारा घर से बाहर निकलना जरूरी है। मगर हां, निकलते वक्त हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। टीकाकरण भी फायदेमंद उपाय है और इस पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। मगर हाल के महीनों में पूरी आबादी को टीका लग पाना संभव नहीं है। इसके अलावा, यह भी अब तक साफ नहीं हो सका है कि टीका लेने मात्र से कोरोना से सुरक्षा संभव है। इसलिए बचाव के बुनियादी उपायों को अपने जीवन में ढालना ही होगा। तभी इस वायरस का हम सफल मुकाबला कर सकेंगे।

प्रवीण कुमार सिंह

मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए नए कानूनों के जरिए बेहतरीन सुधार में जुटी

इस दल में केवल अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अधिकारी हैं। स्पष्ट है कि चीन की चुनौती को बाइडन भी गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान के यकायक हुए इस कथित हृदय परिवर्तन पर भरोसा किया जा सकता है सच यही है कि भारत-पाकिस्तान संकट का मुख्य कारण वह वैचारिक अधिष्ठान है, जो 'काफिर-कुफ्र' अवधारणा से कुप्रेरित है। इस विचार का अंतिम उद्देश्य भारत को आघात पहुंचाना है। अतीत इसका गवाह रहा है। भारत ने जब भी पाकिस्तान के साथ शांति को लेकर कोई पहल की तो उसके कुछ समय बाद ही हमें सीमा पार से आतंकी हमला झेलना पड़ा। इसे देखते हुए भारत को पाकिस्तान के साथ चीन से भी और सचेत रहना होगा।

कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ समय से जारी चंद किसान संगठनों के विरोध-प्रदर्शन के बीच कई अहम तथ्य कहीं पीछे छूट गए हैं। उन पर गौर करने से वस्तुस्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसी कड़ी में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश केंद्र के हालिया बजट पर भी दृष्टि डाली जाए। उसमें कृषि के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसकी तुलना में 2018-19 में यह आवंटन 57,600 करोड़ रुपये था। वह भी पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के 2013-14 के बजट की तुलना में तीन गुना अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गहरे जुनून से प्रेरित सरकार शोर-शराबे से दूर किसानों के उत्थान के लिए मदद का दायरा बढ़ा रही है।

कृषि इनपुट के मोर्चे पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के असर को समझें। यह योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराया जाना था। साथ ही पानी के इस्तेमाल की समग्र दक्षता में सुधार करना भी इसका मकसद था। इसके लिए 'मोर क्रॉप पर ड्रॉप' जैसा प्रेरक नारा गढ़ा गया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय में इसके लिए मिशन निदेशालय गठित किया गया। सिंचाई लाभ कार्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए 99 से अधिक परियोजनाएं भी चिन्हित की गईं। परिणामस्वरूप 2019 तक कुल 76 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे फायदा मिला। इसमें नाबार्ड के दीर्घकालिक सिंचाई कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये की मदद उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा इस योजना के तहत माइक्रो-इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया। इससे सूक्ष्म सिंचाई का क्षेत्र 8.13 लाख हेक्टेयर से बढ़कर करीब 90 लाख हेक्टेयर हो गया। निश्चित रूप से इसका श्रेय सूक्ष्म सिंचाई निधि कोष को जाता है, जिसका बजट हाल में दोगुना कर 5,000 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार ने पूरे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सराहनीय पहल भी की है। इससे किसानों को उनकी उर्वरक इनपुट लागत को कम करने के लिए सालाना प्रति हेक्टेयर औसतन 5,000 रुपये मिले। सरकार जीरो-बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। आंध्र प्रदेश ने 2024 तक 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर शत प्रतिशत जीरो-बजट प्राकृतिक खेती की योजना तैयार की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का जोखिम कम करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें किसान के लिए बहुत कम प्रीमियम भुगतान (फसल के अनुसार तकरीबन 1.5-2 प्रतिशत) तय किया गया है। इसके चलते खरीफ फसल के लिए बीमा कवरेज में 2.72 करोड़ हेक्टेयर से 3.75 करोड़ हेक्टेयर की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ऐसी ही बढ़ोतरी समग्र बीमा राशि में भी हुई। फसल की अच्छी कीमत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने ई-नाम (ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) योजना के माध्यम से कृषि मार्केटिंग में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसके जरिये खरीदार देश की किसी भी मंडी से कोई भी कृषि उपज खरीद सकते हैं। साल 2020 की शुरुआत तक 18 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की तकरीबन एक हजार कृषि मंडियों को ई-नाम नेटवर्क से जोड़ा जा चुका था। इस साल हजार से ज्यादा और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाना है। दूसरी तरफ, अब एपीएमसी या कृषि मंडी अपने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से भी मदद हासिल कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बुनियादी ढांचा फंड के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 'किसान रेल' की शुरुआत भी ऐसा ही एक कदम है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह कृषि उपज के लिए कोल्ड चेन बनाने में बहुत मददगार होगी।

किसानों को बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में 10,000 से ज्यादा नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने पर जोर दे रही है। ऐसे संगठनों को सरकार का समर्थन उन्हें बाजार में बेहतर शर्तों पर मोलभाव की क्षमता प्रदान करेगा, जबकि फाइनेंसिंग उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सरकार ने 2019-20 में खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया ताकि इन फसलों के लिए राष्ट्र स्तर पर आकलित औसत उत्पादन लागत का तकरीबन 1.5 गुने के स्तर पर पहुंच सके। इसमें गेहूं का ही मामला ले लें, जिसकी एमएसपी 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई, जिससे कुल रिटर्न 109 प्रतिशत हो गया। प्रतिशत के लिहाज से ही किसान को पिछले वर्ष की एमएसपी में 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिली।

आमदनी में इजाफे के लिए सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इसमें छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना की मदद दी जाती है। इस योजना में अब देश के सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2021 में तकरीबन 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए 65,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसके अलावा मोदी सरकार ने दूसरे उपायों जैसे कि डेयरी के जरिये किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली पहल की है। वर्ष 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता 5.35 करोड़ टन से बढ़ाकर 10.8 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन फ्लड (डेयरी विकास कार्यक्रम) की ही तरह ऑपरेशन ग्रीन्स (आलू-प्याज-टमाटर का समन्वित उत्पादन कार्यक्रम) की शुरुआत गेहूं और धान से इतर फसलों की खेती को बढ़ावा देकर देश में कृषि फसलों का संतुलन कायम करने में दूरगामी असर वाली होगी।

नए कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शनों पर बहुत अखबारी स्याही खर्च की गई है, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों की मदद के लिए जो काम किया है, शायद ही उस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। काम के इतने व्यापक दायरे को देखते हुए इस विषय पर किसी भी सरकार की आलोचना करना बहुत आसान है। हालांकि विचारशील लोगों को उन बेहतरीन सुधारों और कदमों पर गौर करना चाहिए, जो सरकार भारत के कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार गरीब किसानों की जरूरतों से परिचित है और यह सुनिश्चित करने की गहराई से कोशिश कर रही है कि अगले दशक तक उनकी आमदनी बढ़ जाए।

मैपिंग नीति में बदलाव भारत के लिए रक्षा और गैर-रक्षा से जुड़े क्षेत्रों को बनाएगा आत्मनिर्भर

मैपिंग नीति में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने नियंत्रित भू-स्थानिक डाटा तक पहुंच पर प्रतिबंध को हटा लिया है। इस बदलाव से पहले व्यक्तियों और कंपनियों को भू-स्थानिक सूचना विनियमन अधिनियम, 2016 के तहत मानचित्रण डाटा के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। भू-स्थानिक डाटा और सेवाओं को प्राप्त करने व सृजित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रलय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत व्यवसायों और नवप्रवर्तकों को डिजिटल भू-स्थानिक डाटा और मानचित्रों को एकत्रित करने, स्टोर करने, तैयार करने, प्रसार करने, प्रकाशित करने और उसे अद्यतन करने से पहले उसके पूर्व अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।

भौगोलिक क्षेत्र की सटीक जानकारी आधुनिक डिजिटल प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह उन उद्योगों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है जो ई-कॉमर्स, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स व परिवहन जैसी स्थान-आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। यह अर्थव्यवस्था के अधिक परंपरागत क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण और अचल संपत्ति व खदान जैसे क्षेत्रों के लिए भी जरूरी है। यह कदम कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि इस क्षेत्र में विदेशी कंपनी पर निर्भरता कम करनी होगी जो सामरिक दृष्टि से भी अहम है। चिंताजनक यह है कि भू-स्थानिक डाटा प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारतीय स्टार्ट-अप अभी भी काफी पीछे हैं। वहीं इससे जुड़े कुल 140 स्टार्ट-अप राजस्व के मामले में इस क्षेत्र की बड़ी कंपनी गूगल से काफी पीछे हैं। ऐसे में मैपिंग नीति में हुए व्यापक बदलाव एक प्रभावी कदम साबित होगा। दरअसल भारत में ई-कॉमर्स के विकास की गति काफी तेज है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार वर्ष 2024 तक भारत में ई-कॉमर्स से जुड़े क्षेत्रों का कारोबार सौ अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। महत्वपूर्ण है कि ई-कॉमर्स से जुड़े क्षेत्र की निर्भरता अभी भी कुछ सीमित विदेशी संस्थाओं पर है जो भौगोलिक डाटा उपलब्ध कराते हैं।

ऐसे में इस क्षेत्र में आवश्यक पहल करने की जरूरत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रलय द्वारा हाल ही में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर जो चीज आसानी से उपलब्ध है, उसे भारत में प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है और इसलिए जो भू-स्थानिक डाटा प्रतिबंधित था, भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। भारतीय संस्थाएं भू-स्थानिक डाटा के प्रयोग के लिए विदेशी संस्थाओं और विदेशी-स्वामित्व वाली संस्थाओं को लाइसेंस दे सकती हैं। यह भी सही है कि वैश्विक स्तर पर हो रहे अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान ने देश की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए एक चुनौती उत्पन्न कर दी है। ऐसे में विदेश आधारित इमेजिंग उपग्रह पर निर्भरता को कम करने की दिशा में अपेक्षित सुधार आवश्यक हो गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में गूगल पर उपलब्ध भारत के सभी रक्षा ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को देश के लिए खतरा बताया गया था, वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में पाया कि 26/11 के मुंबई हमले में भी आंतकियों द्वारा जानकारी जुटाने के लिए इन्हीं माध्यमों का उपयोग किया गया था।

मुद्दा यह है कि जब तक भारत भौगोलिक डाटा प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, तब तक इस क्षेत्र को नियंत्रित करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा विकसित भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जिसे भारतीय क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जबकि यह भारतीय मुख्य भूमि से 1,500 किमी के आसपास तक नेविगेशन आधारित जानकारी देने में सक्षम है। इसका उपयोग स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन के लिए किया जा रहा है, जबकि आपदा प्रबंधन, मैपिंग और भू-स्थानिक डाटा के प्रयोग आधारित जुड़े क्षेत्रों में किया जा रहा है। भू-स्थानिक डाटा पृथ्वी की सतह पर किसी भी विशिष्ट स्थान से संबंधित विशिष्ट जानकारी होती है, ऐसे में भारत में कई आधारभूत संरचनागत विकास में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। औद्योगिक गलियारों या नदियों के लिंक जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के दौरान सटीक भू-स्थानिक डाटा महत्वपूर्ण है।

साथ ही, लॉजिस्टिक्स और उन्नत शहरी परिवहन व्यवस्था आधारित स्मार्ट-सिटी के विकास में इस डाटा का प्रयोग काफी उपयोगी हो गया है।विगत वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों और निगरानी के लिए भौगोलिक सत्यापन को अनिवार्य बनाया जा रहा है। ऐसे में योजनागत निर्माण कार्यों का सटीक अनुमान के साथ उसके प्रबंधन में भी इस डाटा का प्रयोग काफी बढ़ा है। यह बदलाव भू-स्थानिक डाटा तक अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की पहुंच आसान होगी, जबकि देश में विकसित इमेजिंग उपग्रह और सटीक भू-स्थानिक जानकारी उपलब्ध करने में सक्षम है।

वायरस की लुकाछिपी

देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आ रही तेजी अब गंभीर रूप लेती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,291 नए मामले दर्ज किए गए जो इस साल एक दिन में दर्ज हुई अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र की है। पिछले 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में 16,620 नए केस दर्ज हुए जो कुल नए केसों का 63.21 फीसदी है। देश में अभी कुल 2.12 लाख एक्टिव केसों में से 1.27 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। गौर करने की बात यह भी है कि सोमवार को नए केसों की संख्या में दिख रही तेजी कोई अपवाद या अचानक आई एक दिन की तेजी नहीं है। यह लगातार पांचवां दिन है जब नए केसों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जाहिर है, इस तथ्य से आंखें नहीं चुराई जा सकतीं कि कोरोना के मोर्चे पर हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं। अभी दो-तीन दिन पहले ही यह कहा गया था कि यह पैंडेमिक अब एंडेमिक बन रहा है, यानी कोरोना महामारी अब खात्मे की ओर है। हालांकि तब भी विशेषज्ञों ने इसे अति उत्साह बताते हुए ऐसे दावों से बचने की सलाह दी थी। इन दावों का प्रभाव हो या न हो, पर आम जनता के बड़े हिस्से में यह धारणा बन गई लगती है कि कोरोना अब कोई खास चुनौती नहीं रही। इसका संकेत हमें देश के अलग-अलग हिस्सों में भीड़ के व्यवहार में दिख रहा है।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ हुए टी-20 मैच में दर्शकों की भीड़ हैरान कर रही थी। उस भीड़ में मास्क से ढका एक भी चेहरा खोजना मुश्किल था। अन्य राज्यों की तो बात ही छोड़िए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी दादर के भीड़ भरे बाजार की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बहरहाल, देश में टीकाकरण अभियान जरूर तेजी पर है। पिछले हफ्ते रोज औसतन 12.6 लाख डोज दिए गए। तुलनात्मक रूप से देखें तो अमेरिका के बाद यह संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहां रोज औसतन 25 लाख डोज दिए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच यूरोपीय देशों में ऐस्ट्राजेनेका-ऑक्सफर्ड वैक्सीन का बढ़ता विरोध भी कई सवाल खड़े कर रहा है। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, लिथुआनिया, एस्तोनिया, आइसलैंड जैसे कई देशों में इस टीके के साइड इफेक्ट्स को लेकर आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस पर तात्कालिक रूप से रोक लगा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जरूर आश्वस्त किया है कि टीके को लेकर आशंकाएं पालने या इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने इसके भारतीय संस्करण कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की और गहरी समीक्षा करने का फैसला किया है। ऐसे में जब आने वाले कुछ दिन वैक्सीन को लेकर अनिश्चितता बढ़ाने वाले हो सकते हैं, मास्क और दो गज दूरी जैसे आजमाए हुए उपायों पर अमल की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।

निःसंदेह भारत में कई क्षेत्रों में सुधार जरूरी हैं, पर पाकिस्तान से तुलना करना शरारत है

कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसके यहां कोई समस्या नहीं, लेकिन यह स्वीकार नहीं कि कमियों को इंगित करने के नाम पर देश विशेष के प्रति दुर्भावना का प्रदर्शन किया जाए। पश्चिमी देशों की कथित स्वतंत्र संस्थाओं से ज्यादा वहां का मीडिया भारत के प्रति दुर्भावना से भरा है। कई बार तो यह दुर्भावना नस्ली रंगत लिए दिखती है। यह सिलसिला तब तक कायम रहने वाला है, जब तक भारत में भी ऐसी संस्थाएं और समूह सक्रिय नहीं होते, जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि की खामियों को रेखांकित करने का काम करें।

भारत का अंतरराष्ट्रीय कद जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे उसे नीचा दिखाने या बेवजह नसीहत देने का काम भी तेज हो रहा है। इस काम में विभिन्न पश्चिमी देश, उनकी संस्थाएं और उनका मीडिया भी शामिल है। कोरोना संक्रमण का कहर टूटने के बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया के एक बड़े हिस्से का मानना था कि भारत में लाशों के ढेर लग जाएंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो यही मीडिया इस पर हैरानी जताने लगा कि आखिर बड़ी आबादी वाले देश में इतने कम लोग कैसे मरे? कुछ यह आशंका जाहिर करने में जुट गए कि कहीं कोविड से मरे लोगों की मौतों को छिपाया तो नहीं गया? उन्हें इससे निराशा हुई कि और सब चीजें तो छिपाई जा सकती हैं, लेकिन मौतें नहीं। जब भारत ने कोविड रोधी टीका बनाने में सफलता हासिल कर ली तो उसमें भी नुक्स निकालने की कोशिश की गई और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद ऐसे सवाल खड़े किए गए कि आखिर तीसरे चरण के ट्रायल का विवरण सामने आए बिना उसे मंजूरी कैसे दे दी गई? ऐसे सवाल उठाने वालों को तब निराशा हुई, जब पता चला कि ऐसे और भी टीके थे, जिन्हें इसी तरह मंजूरी मिली। कुछ समय पहले तक इसकी आशंका थी कि इस तरह के सवाल उठेंगे कि भारत अपने लोगों को टीका लगाए बगैर दूसरे देशों को टीके की आपूर्ति क्यों और कैसे कर रहा है, लेकिन प्रतिदिन दस लाख से अधिक लोगों के टीकाकरण के बाद ऐसे सवाल उठाने की तैयारी कर रहे परसंतापी कसमसा कर रह गए। किसी न किसी बहाने भारत को कठघरे में खड़े करने की

उनकी मंशा पूरी कर दी अमेरिकी संस्था 'फ्रीडम हाउस' की उस रपट ने, जिसमें कहा गया है कि अब भारत स्वतंत्र देश नहीं रहा।

अमेरिकी सरकार के पैसे से चलने वाले 'फ्रीडम हाउस' ने भारत को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र देश की श्रेणी में रख दिया है। भारत को 100 में से 67 अंक दिए गए हैं। 71 अंक होते तो भारत का स्वतंत्र देश का दर्जा बरकरार रहता। स्वतंत्र देश के दर्जे से मतलब है ऐसा देश, जहां लोगों को पर्याप्त राजनीतिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो और जहां विभिन्न संस्थाएं भी स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हों। निःसंदेह भारत में सब कुछ ठीक नहीं और कई क्षेत्रों में सुधार की सख्त जरूरत है, लेकिन उसे उस पाकिस्तान के समकक्ष रखना शरारत के अलावा और कुछ नहीं, जहां का शासन सेना चलाती है और जहां अल्पसंख्यक संवैधानिक तौर पर दोयम दर्जे के नागरिक हैं।

ऐसा लगता है कि फ्रीडम हाउस वाले भारत का दर्जा घटाने पर तुले थे, क्योंकि इस आधार पर भी अंकों में कटौती की गई कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा के सदस्य बन गए और एमनेस्टी इंटरनेशनल सरीखे संदिग्ध इरादों वाले संगठनों या फिर ऐसे ही अन्य गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदे का मनमाना इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की कठिन हालात में घर वापसी को भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इससे इन्कार नहीं कि लॉकडाउन के समय तमाम मजदूरों को विपरीत परिस्थितियों से दो-चार होना पड़ा, लेकिन सरकार ने जानबूझकर उनके सामने मुश्किलें नहीं खड़ी कीं। देशद्रोह कानून का अनावश्यक इस्तेमाल करने के लिए भारत की आलोचना की जा सकती है, लेकिन ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि इंटरनेट सेवा बाधित करने का काम लोगों को जानबूझकर तंग करने के लिए किया गया। फ्रीडम हाउस को नागरिकता संशोधन कानून रास नहीं आया, लेकिन उसने यह देखने से इन्कार किया कि इस कानून के विरोधी किस तरह सौ दिन तक एक व्यस्त सड़क को घेर कर बैठे रहे।

फ्रीडम हाउस जैसी संस्थाएं और भी हैं, जो विभिन्न मसलों पर रेटिंग के जरिये भारत को कठघरे में खड़ा करने का काम करती हैं। जैसे तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने यह जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है कि भारत समेत दुनिया के अन्य देशों को उनसे सीख लेनी चाहिए, उसी तरह कुछ देशों की सरकारें और वहां के राजनीतिक दल भी स्वयंभू मार्गदर्शक मान गए हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री की टिप्पणी इसी का नतीजा थी। यह वही कनाडा है, जो विश्व व्यापार संगठन में भारत सरकार की ओर से अपने किसानों को सब्सिडी देने का विरोध करता है, लेकिन अपने यहां के खालिस्तानियों को खुश करने के लिए कृषि कानून विरोधी आंदोलन को हवा देता है। बीते दिनों ब्रिटेन की संसद में भी इन कानूनों पर बहस के बहाने भारत पर हमला बोला गया। इस बहस का आधार बना एक लाख से अधिक लोगों का अनुरोध पत्र। इस बहस से यह साफ हुआ कि ब्रिटेन में कुछ ताकतें ऐसी हैं, जो भारत पर निशाना साधने के लिए आतुर थीं। ब्रिटेन की तरह अमेरिका में भी सांसदों का एक समूह ऐसा है, जिसे लगता है कि उसे भारत को हर मामले में नसीहत देने का अधिकार हासिल है।

भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। आगे भी किसी न किसी बहाने भारत को यह बताया जाएगा कि उसके यहां यह या वह गड़बड़ है। कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसके यहां कोई समस्या नहीं, लेकिन यह स्वीकार नहीं कि कमियों को इंगित करने के नाम पर देश विशेष के प्रति दुर्भावना का प्रदर्शन किया जाए। पश्चिमी देशों की कथित स्वतंत्र संस्थाओं से ज्यादा वहां का मीडिया भारत के प्रति दुर्भावना से भरा है। कई बार तो यह दुर्भावना नस्ली रंगत लिए दिखती है। यह सिलसिला तब तक कायम रहने वाला है, जब तक भारत में भी ऐसी संस्थाएं और समूह सक्रिय नहीं होते, जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि की खामियों को रेखांकित करने का काम करें।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया के साथ गुवाहाटी में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले असम की यात्रा के दौरान कामाख्या मंदिर में।

यूपी में चार चरणों में जिलेवार होंगे पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन

लखनऊ । उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं को चारों मतपत्र एक ही मतपेटी में डालने की सुविधा मिलेगी। चार चरणों में जिलेवार चुनाव कराए जाएंगे। प्रत्येक मंडल में एक चरण में एक ही जिले के सभी विकास खंडों में चारों पदों के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान दल में एक महिला होने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने को कहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्येक मतदान स्थल पर तीन की जगह दो मतपेटी रखने को कहा है। चुनाव चिह्न आवंटन के बाद प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने पर ही संबंधित मतदान स्थल पर तीन

मतपेटियां रखी जाएंगी। एक ही मतपेटी में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के अलग-अलग रंग के मतपत्रों को डाला जाएगा।

पहली मतपेटी भरने के बाद दूसरी का उपयोग किया जाएगा। तीसरी मतपेटी की आवश्यकता पडने पर पीठासीन अधिकारी संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित मतदान स्थल पर तीसरी मतपेटी उपलब्ध कराएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतदान के दिन मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान वाहन में पर्याप्त अतिरिक्त मतपेटी रखने के निर्देश दिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक जिले के सभी विकासखंडों में एक ही चरण में चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। किसी मंडल में जिलों की संख्या चार से अधिक हैं तो वहां किसी एक चरण में दो जिलों में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। पोलिंग पार्टी में भी पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त तीन मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे।

दूसरे जिलों के कर्मचारी लगाए जाएंगे ⁼ राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी विकास खंडों में एक साथ चुनाव कराने से मतदान दलों के लिए कर्मचारियों-अधिकारियों की आवश्यकता होगी तो मंडल के दूसरे जिले से पूरा किया जाएगा। एक मंडल के कर्मचारियों को एक से दूसरे जिले में उपलब्ध कराने का निर्णय मंडलायुक्त करेंगे।

साफ्टवेयर से होगी नियुक्ति ⁼ पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर ईएसडी सॉफ्टवेयर में प्री-एनालिसिस टूल उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान दलों के लिए कर्मचारियों का आकलन मतदान दलों की संख्या से 20 प्रतिशत अधिक के आधार पर किया जाएगा।

लाल, हरा, नीला व सफेद होंगे मतपत्र ⁼ मतदाताओं की सुविधा के लिए अलग अलग पदों के लिए चार रंग के मतपत्र प्रकाशित किए जाएंगे। कुल 52.5 करोड़ मतपत्र प्रकाशित कराए गए है। मतदान कर्मियों को उनके जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा।

संक्षिप्त खबर

बिहार में आइसोलेशन सेंटर दोबारा शुरू, होली पर दूसरे राज्यों से आनेवाले को रखा जाएगा

पटना । राजधानी में होली पर कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वालों की जांच के साथ उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद सिविल सर्जन ने होटल पाटलिपुत्र अशोक में 165 बेड के आइसोलेशन सेंटर को दोबारा दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। संक्रमितों की संख्या बढने पर पटनासिटी स्थित राधास्वामी मंदिर में भी फिर से 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर शुरू करने की बात कही जा रही है।

दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जिले में बनाए गए 17 आइसोलेशन सेंटर में से होटल पाटलिपुत्र अशोक को छोड़कर 16 को बंद कर दिया गया था। आधा दर्जन से अधिक राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे कॉल सेंटर संचालित करने के साथ आइसोलेशन सेंटर दुरुस्त करने के निर्देश सभी सिविल सर्जन को दिए हैं। वहीं, मेडिकल कॉलेजों को 24 घंटे कोविड वार्ड में इलाज की तैयारी रखने को कहा गया है।

24 घंटे डॉक्टर की नियुक्ति- सविल सर्जन डॉ. विभा कुमारी सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण अब एक वर्ष पुराना हो गया है। बहुत से लोग इससे बचाव के उपायों को अपनी आदत बना चुके हैं। ऐसे में अन्य प्रदेशों में संक्रमण के मामले बढ़ते देखकर एहतियातन तैयारी की जा रही है। बाहर से आने वाले जो संक्रमित मिलेंगे और उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखने की जरूरत होगी तो 165 बेड का होटल पाटलिपुत्र अशोक पूरी तरह तैयार है। वहां 24 घंटे डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। यदि जरूरत होगी तो राधा स्वामी मंदिर में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर एक दिन में शुरू किया जा सकता है। गत वर्ष मई से दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक जिले में 17 आइसोलेशन सेंटर थे। वहां 2700 लोगों को रखने की व्यवस्था थी। इन सेंटरों पर संक्रमितों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन, दवाएं और नाश्ता-खाना-पीना सब दिया जाता था। अधिकांश सेंटर अक्सर खाली रहने के कारण होटल पाटलिपुत्र अशोक को छोड़कर अन्य सभी आइसोलेशन सेंटर बंद कर दिए गए थे।

पटना में स्वर्गवासी हो चुके लोगों को इंदिरा आवास आवंटित, एक ही परिवार में चार लोगों को मिला लाभ

पटना/दनियावां । गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए मदद देने वाली योजना में बड़ी गड़बड़ी की खबर है। यह खबर है बिहार की राजधानी पटना से। पटना जिले के दनियावां प्रखंड की शाहजहांपुर पंचायत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में दिवंगत हो चुके लोगों को भी आवास बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। दूसरी तरफ एक ही परिवार के चार लोगों को आवास आवंटित करने का मामला भी सामने आया है। और तो और सामान्य जाति के परिवार का चयन ओबीसी के कोटे में कर लिये का आरोप भी लग रहा है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के चयनित लाभार्थियों की सूची में भारी अनियमितता की बात सामने आई है। पता चला है कि एक ही परिवार के चार व्यक्तियों को आवास का आवंटन दे दिया गया है। इन लाभुकों में दो व्यक्ति चनक मांझी व सिंहेश्वर मांझी भी हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। इनके अलावा कमला देवी और सिंहेश्वर सिंह राजपूत जाति से आते हैं। इन्हें ओबीसी श्रेणी में चयनित कर लिया गया है। इस सूची में दो मृत व्यक्तियों का नाम अंकित है, जिनमें पहला नाम मसनदपुर निवासी चनक मांझी का, जिनकी मृत्यु चार पांच वर्ष पूर्व ही हो गई है। वहीं, दूसरा उनकी पत्नी का है, उनकी भी मृत्यु चार वर्ष पूर्व हो गई है। दूसरा शाहजहांपुर निवासी सिंहश्वर सिंह पिता भरोसा सिंह इनकी भी मृत्यु दो तीन वर्ष पहले हो चुकी है। इनका चयन ओबीसी श्रेणी लिखा गया हैं।

मजेदार बात यह है कि सिंहेश्वर सिंह जनरल जाति (राजपूत) से हैं, जबकि उनको ओबीसी कर दिया गया है। सूत्रों की मानें तो दनियावां प्रखंड में कार्यरत आवास सहायक प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के चयन में बिचौलियों के बल पर ही योजना का चयन करते हैं। इससे गरीब लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। इस सूची के प्रकाशन ने इनकी पोल खोल दी है। इस संबंध में बीडीओ पंकज कुमार निगम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जांच कर नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी।

यूपी के SC-OBC के लिए बड़ी खबर, नौकरी की परीक्षा की तैयारी निशुल्क कराएगा सेवायोजन विभाग; 20 तक होगा आवेदन

लखनऊ। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक तंगी की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को सेवायोजन विभाग निशुल्क कोचिंग कराएगा। लालबाग के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में 20 तक आवेदन किया जा सकता है। 23 को अनुसूचित जाति व जनजाति व 24 को पिछड़ा वर्ग के युवाओं का साक्षात्कार होगा।

ऐसे होगा प्रवेश- आर्थिक रूप से कमजोर इंटर पास 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं का लोवर डिविजनल क्लर्क के पदों पर तैनाती के लिए होने वाली परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। 60 सीटों वाली इस कोचिंग में अनुसूचित जाति व जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं का प्रवेश होगा। एक अप्रैल से 25 मार्च तक कोचिंग में चलेगी। अनुसूचित जाति के बच्चों को 200 रुपये महीना वजीफा भी समाज कल्याण विभाग देता है। एक छात्र को एक बार में 200 रुपये स्टेशनरी खरीदने के लिए अलग से दिए जाते हैं।

जिला सेवायोजन अधिकारी शशि तिवारी के मुताबिक, कोचिंग का संचालन सुचारू रूप से संचालन के लिए अनुदेशकों की तैनाती की गई है। 20 मार्च तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। आवेदन के इच्छुक बेरोजगार लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के कमरा संख्या आठ से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने वाले युवाओं का 23 और 24 मार्च को साक्षात्कार होगा।

करियर काउंसिलिंग कर संवार रहे भविष्य- सेवायोजन विभाग की ओर से पॉलीटेक्निक, इंटर कॉलेज और महाविद्यालय में करियर काउंसिलिंग की ऑफलाइन शुरुआत हो गई है। काउंसिलिंग प्रभारी व जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्रा ने बताया कि शिविर के माध्यम से युवाओं को करियर के चुनाव की जानकारी दी जा रही है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन और नौकरी पाने की संभावनाओं की जानकारी भी दी जाती है।

यूपी में एक और बम्पर शिक्षक भर्ती : यूपी टीईटी का रिजल्ट आते ही होगी घोषणा; भरे जाएंगे 51 हजार खाली पद

लखनऊ । उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2020 कराने का ऐलान बेसिक शिक्षा विभाग ने कर दिया है। इसे बेसिक शिक्षा के प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती की आहट माना जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में 51,112 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यह दावा सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कर चुकी है। ऐसे में पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती होना लगभग तय है।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 25 जुलाई को होना प्रस्तावित है। पहले तैयारी थी कि यूपी टीईटी के बाद ही एडेड जूनियर हाईस्कूल और

प्राथमिक स्कूलों की भर्ती कराई जाएगी लेकिन, जूनियर स्कूलों में इधर लंबे समय से सीधी भर्ती नहीं हुई थी, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की अधिक तादाद को देखते हुए यह भर्ती बिना टीईटी के ही कराने का निर्णय हुआ।

विधानसभा चुनाव के पहले दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र : प्राथमिक स्कूलों की भर्ती इधर तय अंतराल में हो रही हैं, इसके लिए पात्रता परीक्षा कराना जरूरी है। इसलिए जुलाई या फिर अगस्त में शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है, ताकि कुछ ही दिनों में लिखित परीक्षा कराकर परिणाम घोषित हो और विधानसभा चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र वितरित हो सकते हैं।

डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी की आस में बैठे : प्रतियोगी नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद अगली भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया था। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 51,112 पद रिक्त होने की बात स्वीकार की है। इधर, करीब दो लाख से अधिक डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी की आस लगाए बैठे हैं।

शिक्षामित्रों को भी भर्ती का इंतजार : शिक्षामित्रों को भी अगली भर्ती का इंतजार है। वजह, सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को शिक्षामित्रों को एक और भर्ती में अवसर देने के आदेश दिए हैं। 68,500 व 69,000 भर्ती में बामुश्किल 15 हजार शिक्षामित्रों को नौकरी मिल सकी है। जुलाई 2017 में 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था। उसके बाद से शिक्षामित्र नई भर्ती से उम्मीद लगाए बैठे हैं।

यूपी टीईटी 25 जुलाई को : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा इस साल 25 जुलाई को आयोजित होगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। सुबह 10 से दोपहर 12.30 बजे तक होने वाली पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। दोपहर 2.30 से शाम पांच बजे तक दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। परीक्षा का रिजल्ट 20 अगस्त को घोषित होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपीटीईटी-2020 के आयोजन की समय सारिणी तय करते हुए इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। यूपीटीईटी के आयोजन के लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई दोपहर से शुरू होगा।

पंजाब में किसान केंद्र सरकार के सीधे पेमेंट के फैसले से खुश, बेचैन आढ़ती बनाएंगे नई रणनीति

चंडीगढ़ । पंजाब के किसान कृषि कानूनों खिलाफ आंदोलन के बीच केंद्र सरकार के एक फैसले से खुश हैं। केंद्र सरकार ने फसलों की खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खाते में आनलाइन पेमेंट करने के निर्देश दिए हैं। इससे राज्य के किसान खुश हैं। दरअसल पंजाब के किसान लंबे समय से फसल खरीद की सीधी अदायगी की मांग कर रहे थे। लेकिन, इस निर्देश से आढ़तियों में बेचैनी है और वे चाहते हैं कि किसान संगठन इसका विरोध करें।

बताया जाता है कि पंजाब में भारतीय किसान यूनियन राजेवाल को छोड़कर ज्यादातर किसान इससे खुश हैं, लेकिन केंद्र सरकार के इन निर्देश के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं। इस बारे में आढ़ती संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा से भी बात की है। बताते हैं कि बुधवार को दिल्ली में आढ़ती एसोसिएशन की किसान संगठनों के साथ बात होगी।

आढ़ती संगठन लगातार किसानों से बात करके उनके पक्ष में बयान देने को कह रहे हैं लेकिन अभी तक बलबीर सिंह राजेवाल के अलावा किसी ने भी आढ़तियों के पक्ष में आवाज नहीं उठाई है। दरअसल ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं है क्योंकि लंबे समय से किसान ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी फसल का भुगतान सीधा किया जाए न कि आढ़तियों के माध्यम से।

उधर, किसानों को सीधी अदायगी को लेकर सरकार ने भी अभी कोई मन नहीं बनाया है। पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री भारत भूषण आशू ने कृषि और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की।

इसमें किसानों को सीधी अदायगी करने, भू रिकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने आदि पर चर्चा की गई। आढ़तियों ने यह मामला केंद्र के पास उठाने और किसानों को अदायगी उनके मार्फत करने के लिए दबाव बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आढ़ती एसोसिएशंस को मीटिंग के लिए 22 मार्च का समय दिया है।

दरअसल केंद्र सरकार एफसीआई के खर्चों को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उसमें आढ़तियों को दी जाने वाली 2.5 फीसदी आढ़त और सरकार को दिया जाने वाला तीन फीसदी देहाती विकास फंड पर अंकुश लगाना भी शामिल है।

बिहार में जेडीयू कोटे से एमएलसी बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा, लिस्ट में अशोक चौधरी का भी नाम

पटना । बिहार की राजनीति से जुड़ी यह बड़ी खबर है। जनता दल यूनाइटेड ने राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की छह सीटों के लिए नाम तय कर दिए हैं। जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाएगा। इसके साथ अब कुशवाहा को राज्यसभा भेजे जाने के कयासों पर फिलहाल विराम लग गया है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद यह तय हो गया है कि राज्यपाल कोटे के तहत जेडीयू की छह सीटों में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिली है। राज्यपाल कोटे के तहत शेष छह सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं।

जेडीयू ने तय किए एमएलसी के ये छह नाम- मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा,

संजय गांधी, ललन सर्राफ, रामबचन राय, अशोक चौधरी और संजय सिंह को राज्यपाल कोटे से एमएलसी उम्मीदवार बनाया है।

इस लिस्ट में शामिल उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में अपनी पूरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ जेडीयू में आ गए थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था। माना जा रहा था कि जेडीयू उन्हें राज्यसभा भेजेगा, लेकिन इस कयास पर फिलहाल विराम लग गया है। पार्टी ने उन्हें बिहार में एमएलसी बनाने का फैसला किया है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि उन्होंने देश व बिहार के हित में बिना शर्त अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय किया है, लेकिन अब आगे राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें मंत्री बनाए जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं।

जेडीयू की लिस्ट में शामिल अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। वे नीतीश कुमार की सरकार में पहले से मंत्री हैं। उधर, लिस्ट में शामिल नीतीश कुमार के एक और करीबी संजय सिंह पार्टी के प्रवक्ता हैं।

मायावती ने कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक का किया स्वागत, गरीबों को मुफ्त वैक्सीन देने की अपील

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कोरोना वायरस के दोबारा बढ़ने के खतरे के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फिर दोहराया है कि केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था मुफ्त में कराएं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर देश में कोरोना के दोबारा बढ़ने के खतरे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में घातक कोरोना प्रकोप के दोबारा बढ़ने के खतरे के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आज सभी मुख्यमंत्रियों की बुलाई गई बैठक सही व स्वागत योग्य है। वैसे देश में कोरोना टीकाकरण के अभियान को राष्ट्रीय नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारें इसे और तेज व सुगम बनाएं तो बेहतर होगा।

साथ ही, कोरोना प्रकोप के कारण देश की आमजनता को होने वाली

विभिन्न प्रकार की मुश्किलों व परेशानियों आदि को देखते हुए केन्द्र व राज्य सरकारों से खासकर गरीबों, मेहनतकश लोगों व मध्यमवर्गीय परिवारों को फ्री में कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था करने की पुनः बीएसपी की अपील। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आगे लिखा कि कोरोना प्रकोप के कारण देश की आमजनता को होने वाली विभिन्न प्रकार की मुश्किलों और परेशानियों आदि को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से खासकर गरीबों, मेहनतकश लोगों व मध्यम वर्गीय परिवारों को फ्री में कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था करने की पुनः बीएसपी की अपील।

बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले शनिवार को लखनऊ में कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाया था। मायावती ने आम लोगों से अपील की कि वे भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं।

लोगों को उन्होंने कोरोना नियमों का सही से अनुपालन करने व टीका संबंधी सरकारी दावों आदि से इनकार न करके टीकाकरण का पूरा लाभ उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाना ही सर्वोत्तम उपाय है। उन्होंने मांग की कि गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था की जाए।

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना टीकाकरण का यह कहकर विरोध किया था कि वह बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे। जब उनकी सरकार आएगी तो वह लोगों को मुफ्त में टीका लगवाएंगे। यही नहीं सरकार से यह भी पूछा था कि वह आम लोगों को कब से मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी। फिलहाल इससे इतर बसपा सुप्रीमो ने लोगों से टीका संबंधी सरकारी दावों आदि से इनकार न करके टीकाकरण का लाभ उठाने की अपील की है।

अब सात हजार करोड़ तक लोन ले सकेंगी बिजली कंपनियां; थारू समुदाय को भी पक्के मकान

लखनऊ । उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड व विद्युत वितरण निगम अब सात हजार करोड़ रुपये तक का अधिकतम लोन ले सकेंगी। वह इसकी मदद से आत्मनिर्भर भारत योजना के तरह केंद्रीय विद्युत उत्पादकों, केंद्रीय पारेषण उत्पादकों, आइपीपी व आरई जनरेटर की 30 जून 2020 के देयकों का भुगतान कर सकेंगी।

कैबिनेट ने अतिरिक्त विशेष दीर्घकालीन ट्रांजिशनल ऋण की अधिकतम धनराशि सात हजार करोड़ रुपये आरईसी, पीएफसी एवं बैंकों से पावर कारपोरेशन व विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यही नहीं पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों द्वारा लिए जाने वाले ऋण के आहरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल ऋण के ब्याज एवं अन्य देयों सहित संपूर्ण भुगतान के लिए शासकीय गारंटी उपलब्ध कराने तथा विषम परिस्थितियों को देखते हुए गारंटी शुल्क माफ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार की ओर से आवश्यक वचनबद्धताएं, कार्य योजना निर्गत करने तथा चतुर्पक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग को अधिकृत किए जाने का निर्णय भी लिया गया है।

सहरिया, कोल व थारू समुदाय के लोगों को मिलेंगे पक्के मकान ⁼ बिना मकान या कच्चे जर्जर मकानों आवासों में रहने वाले सहरिया, कोल व थारू समुदाय के गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। योगी सरकार ने गरीबी के दृष्टिकोण से इन समुदाय के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है।

इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में समय-समय पर आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का भी निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव पटना में अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ।

एक नजर

सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले महमूद गजनवी की तारीफ पड़ी भारी, पुलिस ने मौलाना को किया गिरफ्तार

अहमदाबाद । सोमनाथ मंदिर के पास खड़े होकर उसे लूटने वाले महमूद गजनवी को इस्लाम का नेक इंसान बताने वाला वीडियो बनाकर उसे वायरल करने वाले इरशाद रशीद को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें वह कहता है कि आज गजनवी को चोर-लुटेरा कहा जाता है। लेकिन वह इस्लाम का गौरव है। गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर खड़े होकर मौलाना इरशाद रशीद ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया। सोमनाथ ट्रस्ट के प्रबंधक विजय सिंह चावडा ने इस संबंध में पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने उसे पानीपत से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, पुलिस ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। इरशाद ने जो वीडियो वायरल किया, उसमें वह समुद्र किनारे खड़े होकर सोमनाथ मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह वही मंदिर है, जिसे महमूद गजनवी व मुहम्मद कासिम ने फतह किया था। कासिम ने अपनी सेना के साथ इसी सागर को पार कर भारत को जीत लिया था। यह वही समुद्र है जो पाकिस्तान को भारत से जोड़ता है। गजनवी को इस्लाम का नाम रोशन करने वाला तथा महान पुरुष बताते हुए इरशाद आगे कहता है कि उसके इतिहास को पढ़ना व पढ़ाना चाहिए।इरशाद ने कहा है कि चार मई, 2019 को वह गुजरात गया था। सोमनाथ भी घूमने गया। उस दौरान यह वीडियो बनाया था। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने उसके खिलाफ शिकायत की तो उसने दूसरा वीडियो बनाकर जारी कर दिया। इसमें वह अपनी बातों का गलत अर्थ निकालने की बात करने लगा है। वह कहता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब पूजा स्थल हैं। बस सबके तरीके अलग-अलग हैं। उसका मकसद मंदिर का अपमान करना या किसी की भावना को आहत करना नहीं था। मदरसे में पढ़ाता है इरशाद- महमूद गजनवी को महान पुरुष बताने वाला पानीपत का इरशाद रशीद कुटानी रोड पर मदरसे में पढ़ाता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से उससे जुड़े लोग खास हैरान नहीं हैं। उनका कहना है कि वाट्सएप और फेसबुक पर वह इस तरह की आपत्तिजनक बातचीत करता रहता था। उसे कई बार टोका गया, लेकिन नहीं माना। अब मंदिर के सामने खड़े होकर अपना वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो पुराना है लेकिन खतरा था ही कि वह पकड़ा जाएगा।

नीता अंबानी नहीं बनने जा रहीं बीएचयू में प्रोफेसर, रिलायंस इंड्रस्टीज ने बताया फेक न्यूज

मुंबई । नीता अंबानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर नहीं बनने जा रही हैं। रिलायंस इंड्रस्टीज लिमिटेड के प्रवक्ता ने इस खबर को झूठा बताया है। बता दें कि विश्वविद्यालय में नीता अंबानी को विजटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के खिलाफ मंगलवार को छात्र वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। विवाद को बढ़ता देख, अब रिलायंस इंड्रस्टीज की ओर से मामले में सफाई दी है। रिलायंस इंड्रस्टीज के प्रवक्ता ने कहा, नीता अंबानी को बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने की खबर झूठी हैं। उन्हें बीएचयू की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। दअरसल, बीते दिनों रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष और रिलायंस इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी को बीएचयू में महिला अध्ययन का पाठ पढ़ाने का दायित्व देने की तैयारी शुरू की गई थी। ऐसी खबर भी समने आई कि नीता अंबानी को बीएचयू के महिला अध्ययन और विकास केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बीएचयू के सामाजिक विज्ञान संकाय की ओर से 12 मार्च को यह प्रस्ताव दिया गया। उन्हें बनारस सहित पूर्वांचल में महिलाओं का जीवनस्तर सुधारने के लिए बीएचयू में शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ने का आग्रह किया गया था। हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से अब यह साफ कर दिया गया है कि नीता अंबानी को बीएचयू की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

इंडिगो की फ्लाइट में बच्ची का हुआ जन्म, बेंगलुरु से जयपुर जा रही उड़ान में मौजूद डॉक्टर को थैंक्यू कार्ड

बेंगलुरु । बेंगलुरु से जयपुर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में सवार महिला ने बची को जन्म दिया। विमान में सवार गर्भवती महिला को सफर के दौरान प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हालात की गंभीरता को भांपते ही विमान में मौजूद डॉक्टर व क्रू मेंबर्स सक्रिय हुए और विमान में ही डिलीवरी कराने का फैसला किया। इसके बाद महिला ने एक बची को जन्म दिया। जयपुर एयरपोर्ट को तत्काल डॉक्टर व एंबुलेंस की सुविधा का इंतजाम करने की सूचना दे दी गई। इंडिगो ने बयान जारी कर बताया कि मां और बची दोनों स्वस्थ हैं।

फ्लाइट में संयोग से मौजूद थीं डॉक्टर- बची की डिलीवरी में डॉक्टर सुबाहना नजीर ने मदद की जो संयोग से उसी फ्लाइट में सफर कर रहीं थीं (। जयपुर एयरपोर्ट पर डॉक्टर का स्वागत किया गया और जयपुर में इंडिगो स्टाफ ने उन्हें थैंक्यू कार्ड दिया। इंडिगो ने अपने इस काम में योगदान देने वाले अपने स्टाफ की सराहना की। बुधवार सुबह 5.45 बजे बेंगलुरू से रवाना हो यह फ्लाइट करीब सवा दो घंटे में सुबह 8 बजे जयपुर पहुंच गई।

इससे पहले भी सफर में हुआ है बचों का जन्म- ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फ्लाइट में सफर के दौरान किसी बचे का जन्म हुआ है। इससे पहले अक्टूबर, 2020 में इंडिगो की ही दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में एक महिला ने बचे को जन्म दिया था। 2017 में भी इसी तरह से एक महिला ने जेट एयरवेज की फ्लाइट में बचे को जन्म दिया था। जेट एयरवेज ने तो उस बचे के लिए लाइफ टाइम फ्री टिकट का एलान भी किया था। इसी तरह एयर एशिया की फ्लाइट में 2009 में मलेशिया की एक महिला दुबई से मनिला जा रही थी और फ्लाइट में ही उसने एक बची को जन्म दिया था। फिलिपिनो एयरलाइन की ओर से उस नवजात को 10 लाख एयरमाइल्स का उपहार दिया गया था।

दुनिया के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 22 भारतीय, दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी

नई दिल्ली । एजेंसियां । वायु गुणवत्ता का आकलन करने वाली स्वीस संस्था आइक्यूएयर की तरफ से मंगलवार को जारी 'वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2020' यह बताती है कि हम जिस हवा को जिंदगी समझते हैं, वह वास्तव में हमें मौत के करीब ले जा रही है। सूची में शामिल दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 भारतीय हैं। दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर होने के साथ टॉप 10 में भी शुमार रही। हालांकि, पिछले साल 2019 के मुकाबले दिल्ली की वायु गुणवत्ता 15 फीसद सुधरी है। सर्वाधिक प्रदूषित देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश व भारत क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। रैंकिंग में शामिल रहे 106 देश- शहरों की रैंकिंग हवा में पीएम 2.5 की मौजूदगी के आधार पर की गई है। 106 देशों के विभिन्न शहरों की हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 के आंकड़े वहां स्थित निगरानी केंद्रों से लिए गए। अधिकांश केंद्रों का संचालन सरकारें करती हैं। पीएम 2.5 उस प्रदूषक तत्व को कहा जाता है, जिसका व्यास 2.5 माइक्रॉन से कम होता है। दुनिया के करीब आधे प्रदूषित शहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन व भारत में स्थित हैं। देश के 22 सर्वाधिक प्रदूषित शहर- दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा व मुजड्डफरनगर (उत्तर प्रदेश), भिवाड़ी (राजस्थान), फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक व धारूहेड़ा (हरियाणा) तथा मुजड्डफरपुर (बिहार। सूची में भले ही बिसरख जलालपुर को अलग शहर बताया गया हो, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है।

शिनजियांग पहले और दूसरे स्थान पर गाजियाबाद रिपोर्ट में चीन के शिनजियांग को दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया गया है। हालांकि, इसके बाद के नौ सर्वाधिक प्रदूषित शहर भारत के हैं। गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। इसके बाद बुलंदशहर, बिसरख जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, भिवाड़ी व दिल्ली का नंबर आता है। वाहनों से सबसे यादा पीएम 2.5 का उत्सर्जन देश में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में परिवहन, जैविक ईंधन, कोयला से बिजली उत्पादन, उद्योग, निर्माण, कूड़ा व पराली जलाना आदि शामिल हैं। हालांकि, सबसे यादा पीएम 2.5 का उत्सर्जन वाहनों के जरिये होता है। स्वछ ईंधन व यातायात को बढ़ावा देने की जरूरत आइक्यूएयर की रिपोर्ट के संदर्भ में ग्रीनपीस इंडिया के क्लाइमेट कैंपेनर अविनाश चंचल कहते हैं, 'लॉकडाउन के कारण हालांकि दिल्ली समेत कई शहरों की वायु गुणवत्ता आंशिक तौर पर सुधरी है, लेकिन प्रदूषण का स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव बरकरार है।

एनआईए जांच में जब्त हुई मर्सिडीज से मिले कई अहम सुराग, सचिन वझे चलाते थे ये कार

मुंबई । उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर 25 फरवरी को विस्फोटक से लदी कार खड़ी मिली थी। इस केस की जांच लगातार उलझती ही जा रही है। इस मामले में अब पुलिस अधिकारी सचिन वझे का नाम भी शक के दायरे में है। मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली है, जांच एजेंसी एनआईए ने एक मर्सिडीज कार जब्त की है जिसे गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वेज ने इस्तेमाल किया था। जांच में सामने आया है कि इस मर्सिडीज कार को सचिन वझे ही चलाते थे। ये कार मुंबई पुलिस मुख्यालय भी आती थी। कार धुले में रहने वाले भावसार नामक व्यक्ति की थी जिसने बीते माह फरवरी में ही इस कार को एक पोर्टल के माध्यम से बेच दिया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये कार वझे तक कैसे पहुंची।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच में सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज में सचिन वेज को अपने सिर को बड़े रूमाल से ढंकते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को छिपाने के लिए एक ओवरसाइज्ड कुर्ता-पायजामा पहना था, न कि पीपीई किट।

गौरतलब है कि ये कार एनआईए ने मंगलवार को जब्त की थी इसमें केस से जुड़ा काफी सामान भी जब्त किया गया है। इस कार में एक चेक शर्ट भी थी, ये वही चेक शर्ट बतायी जा रही है जिसे पीपीई किट पहने व्यक्ति ने पहना हुआ था। इसके अलावा कार से 5 लाख रुपये कैश भी बरामद हुआ है। इसमें स्कोर्पियो कार का नम्बर प्लेट भी मिला है। एक नोट काउंटिंग मशीन भी बरामद हुई है। कार से प्लास्टिक की एक बोतल में मिट्टी का तेल भी मिला है शक जाहिर किया जा रहा है कि इसका उपयोग पीपीई किट जलाने के लिए किया गया होगा।

नई दिल्ली में संसद के बजट सत्र के दौरान सांसदों ने मंडी के भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो अपने दिल्ली आवास पर मृत पाए गए थे।

प्राइमरी टीचर के पास मिली करोड़ों की संपत्ति, 4 शहरों में मिले जमीन और घर

नई दिल्ली । बड़े-बड़े राजनेताओं और व्यापारियों के घर पर तो छापेमारी और बड़ी संपत्ति मिलना आम है लेकिन क्या आपने कभी किसी स्कूल के प्राइमरी टीचर के घर छापा पड़ते देखा है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, मध्यप्रदेश में बैतूल में ऐसा छापा भी पड़ा और शिक्षक के पास करोड़ों की संपत्ति भी मिली।

दरअसल, यहां के एक प्राइमरी स्कूल टीचर पंकज रामजन्म श्रीवास्तव के पास से सवा पांच करोड़ रुपये की संपत्ति मिली है। मंगलवार को लोकायुक्त भोपाल की 10 सदस्यीय टीम की जांच में ये खुलासा हुआ है। इस टीम ने भोपाल में श्रीवास्तव के मिनाल रेसीडेंसी स्थित मकान और सारणी बगडोना में घरों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी में पंकज के पास बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा और नागपुर में दो दर्जन से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है।

इसमें समरधा में एक प्लॉट, पिपरिया, जाहिरपीर में एक एकड़ जमीन, बैतूल में 8 आवासीय प्लॉट, बागडोना में 6 दुकानें, 10 अलग-अलग गांव में 25 एकड़ जमीन पाई गई है। इनकी कीमत लगभग 5.50 करोड़ है। ये मामले जिसने भी सुना वो चौंक गया कि भला एक प्राइमरी शिक्षक के पास इतना धन- संपत्ति कैसे हो सकते हैं। फिलहाल मामले में जांच चल रही है।

केरल में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, पीसी थॉमस ने छोड़ा एनडीए का साथ

तिरुवनंतपुरम । केरल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पीसी थॉमस ने अब एनडीए का साथ भी छोड़ दिया है। केरल कांग्रेस से अलग हुए पीसी थॉमस की अगुवाई वाले गुट ने आगामी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद मंगलवार देर रात फैसला लिया।

पिछले चुनाव में थॉमस ने कहा कि उनके गुट ने चार विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार भाजपा एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद थॉमस ने कहा कि उनका गुट केरल कांग्रेस के साथ विलय करेगा और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ का हिस्सा होगी। हालांकि, पिछले सप्ताह फिर थॉमस का गुट कांग्रेस से अलग हो गया था और भाजपा में शामिल हुआ था।

पीसी थॉमस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 से 2004 तक कानून और न्याय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वह केरल में मुवत्तुपुझा से 1989 से 2009 तक छह बार लोकसभा सांसद रहे हैं। थॉमस ने 2004 में एनडीए को केरल में अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज करने में मदद की। पिछले पांच चुनावों में थॉमस कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के सहयोगी केरल कांग्रेस (मणि) के उम्मीदवार थे। हालांकि, मई 2001 के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद थॉमस अपने राजनीतिक संरक्षक राज्य के राजस्व मंत्री केएम मणि से अलग हो गए। केरल में 140 सदस्यों वाले विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग है। वहीं दो मई को नतीजे आएंगे।

बता दें कि पिछले सप्ताह पीसी चाको ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया था। केरल में 6 अप्रैल को होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले चाको ने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था। कांग्रेस में पार्टी महासचिव रहे पीसी चाको ने कहा था कि कांग्रेस बिना पतवार की नाव है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। इसके बाद वह शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए थे।

कांग्रेस और भाजपा ने उप चुनाव वाली सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन शुरू, नेताओं को सौंपी जा रही जिम्मेदारी

जयपुर । राजस्थान की चार में से तीन विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले उप चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस व भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। सहाड़ा, वल्लभनगर, राजसमंद और सुजानगढ़ में से वल्लभनगर को छोड़कर तीन सीटों पर चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया। उप चुनाव को लेकर कांग्रेस व भाजपा ने प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन शुरू कर दिया। जीतने योग्य उम्मीदवार की तलाश की जा रही है।

कांग्रेस में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव अभियान संचालन की पूरी कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पास रहेगी। पार्टी आलाकमान ने उन्हे इस बाबत फ्री हैंड दिया है। गहलोत ने चारों चुनाव क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ प्रत्याशी चयन को लेकर प्रारंभिक दौर की बातचीत की है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस चार में से तीन सीटों पर मृतक विधायकों के परिजनों को ही टिकट देने पर विचार कर रही है। इनमें वल्लभनगर से मृतक विधायक गजेंद्र सिंह की पत्नी प्रीती, सुजानगढ़ से स्व.भंवरलाल मेघवाल के पुत्र पंकज को टिकट देने का मानस बनाया गया है।

वहीं सहाड़ा से भी स्व.कैलाश त्रिवेदी के किसी परिजन को टिकट दिया जाएगा। ये तीनों ही कांग्रेस के विधायक थे, इनमें से मेघवाल तो गहलोत सरकार में केबिनेट मंत्री थे। राजसमंद सीट से भाजपा की किरण माहेश्वरी का कोरोना के कारण पिछले माह निधन हुआ था। राजसमंद में प्रत्याशी चयन को लेकर गहलोत ने कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य रघुवीर मीणा से दो दिन पहले लंबी चर्चा की है। कांग्रेस ने चारों सीटों पर मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं को जातिगत आधार पर जिम्मेदारी सौंपी है! मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उप चुनाव को लेकर चर्चा हुई। 20 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद मंत्रियों को चारों सीटों का दौरा करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री चारों क्षेत्रों का एक बार दौरा कर चुके हैं।

उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चारों क्षेत्रों का दौरा कर के आए हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर कार्यकर्ताओं व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है। पूनिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चारों क्षेत्रों में चुनाव प्रभारी बनाया है।

कोरोना काल में 10 लाख से अधिक श्रमिक लौटे थे ओडिशा, श्रम मंत्री ने पेश किया खर्च का ब्यौरा

भुवनेश्वर । कोरोना संक्रमण के समय में राज्य को लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक प्रदेश में आए थे। प्रवासी श्रमिकों की जीविका एवं आराम के लिए सरकार ने धन खर्च कर उनकी मदद की थी। श्रमिकों की जीविका सुरक्षा खर्च के संदर्भ में मंगलवार को खंडपड़ा विधायक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब श्रम मंत्री सुशांत सिंह ने विधानसभा में दिया है।

मंत्री ने सदन के सामने तथ्य रखते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के समय पिछले साल मई महीने से अक्टूबर महीने के बीच राज्य में 10 लाख 7 हजार 330 श्रमिक ओड़िशा लौटे थे। इन श्रमिकों को संगरोध केन्द्र में रखने के बाद तुरन्त सहायता के बाबद मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक व्यक्ति को 2 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है। सरकार ने 2020 अगस्त महीने के अंत तक 6 लाख 73 हजार 79 प्रवासी को सरकार 134.62 करोड़ रुपया आवंटित किया है।

श्रमिकों की जीविका सुरक्षा के लिए मनरेगा मिशन शक्ति जैसी योजना एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे पंचायतीराज एवं पेयजल विभाग, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसुचित जाति मुख्यालय एवं अन्य पिछड़े वर्ग विकास विभाग, महिला एवं शिशु विकास तथा मिशन शक्ति विभाग के अधीन कार्यकारी योजना के माध्यम से कोविड-19 विशेष राहत पैकेज सरकार ने कार्यकारी किया।

इसके अलावा सरकार ने कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग, सुक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्योग, कारखाना, गृह निर्माण तथा नगर विकास, मछली व पशुपालन संसाधन, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा आदि विभाग में प्रचलित योजना तथा कार्यक्रम के अधीन श्रमिकों की जीविका सुरक्षा के लिए रोजगार तैयार किए जाने की सूचना मंत्री ने दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुमोदन क्रम में ओड़िशा कोठाबाड़ी व अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड तरफ से सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 1500 रुपये तक विशेष आर्थिक पैकेज दिया है।

2020 अगस्त महीने तक इस तरह से 4 हजार 689 प्रवासी श्रमिकों को सरकार ने सहायता राशि प्रदान की है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सहायता आवंटन के समय राज्य के बाहर रहने वाले व घर पर अनुपस्थित रहने वाले श्रमिकों को सहायता राशि उनके बैंक खाते में जमा कराए जाने की जानकारी मत्री ने दी।

दूसरों का भी दर्द बांट रहा भारत, अब तक 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज विदेश भेजी

नई दिल्ली । भारत अपने यहां कोरोना टीकाकरण अभियान चलाने के साथ-साथ दूसरे देशों का भी दर्द बांट रहा है। भारत ने अभी तक विदेशों में कोरोना टीके का लगभग 6 करोड़ डोज भेज चुका है। बता दें कि भारत खुद कोरोना टीके का प्रोडक्शन कर रहा है ऐसे में विदेश मंत्रालय के पास कई देशों ने टीके का अनुरोध किया था।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सारा संसार, हमारा परिवार और विज्ञान का लाभ पूरी मानव जाति को मिलना चाहिए की सोच के साथ भारत दूसरे देशों को कोविड-19 रोधी टीका भेज रहा है और यह कदम भारतीयों के हितों को नजरअंदाज कर नहीं उठाया गया है।

72 देशों में पहुंचा कोरोना का टीका

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सोमवार तक भारत ने 72 देशों को टीके की 5.94 करोड़ खुराक भेजी है। उन्होंने भारत में टीकाकरण

की रफ्तार को लेकर उठाए जा रहे सवालों को भी खारिज किया और कहा कि गत सोमवार को सिर्फ एक ही दिन में 3039394 लोगों का टीकाकरण किया गया है।

विपक्ष ने उठाया था सवाल

समाजवादी पार्टी के सुखराम सिंह यादव ने केंद्र सरकार से जानना चाहा था कि वह कोविड-19 रोधी टीका विदेशों में तो भेज रही है लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत कम संख्या में लोगों को टीका लग रहा है। इसके जवाब में हर्षवर्धन ने कहा, भारत के लोगों को टीका लगाया जा रहा है या विदेशों में भेजा जा रहा है.....। किसी भी कीमत पर भारत के लोगों के हितों का नजरअंदाज कर विदेशों में टीका नहीं भेजा जा रहा है।

देश में कम टीकाकरण के दावे को स्वास्थ्य मंत्री ने किया खारीज- हर्षवर्धन ने कहा कि जहां तक भारत में बहुत कम टीकाकरण होने का दावा किया जा रहा है, सिर्फ एक दिन में कल ही 30,39,394 लोगों को टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने टीकाकरण को लेकर जो मानदंड तय किए हैं वह बहुत ही वैज्ञानिक हैं और भारतीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में तैयार किए गए हैं। टीके को लेकर प्राथमिकताएं भी यह समिति ही तय कर रही है।

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी नई दिल्ली में संसद के चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में बोलती हुई ।

अहमदाबाद में पार्क और गार्डन्स को बंद रखने का आदेश, सूरत में सिटी बसों पर लगी रोक

अहमदाबाद । कोरोना संकट के चलते पाबंदियों का दौर शुरू हो रहा है और कई शहरों में प्रशासन ने लोगों की भीड़ न जुटने देने को लेकर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद में सभी पार्कों और गार्डन्स को बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद प्रशासन ने अगले आदेश तक पार्कों पर पाबंदी का आदेश दिया है। शहर की कांकरिया लेक और चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे। इससे पहले मंगलवार को अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। गुजरात भी देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां कोरोना के मामलों में बीते करीब एक महीने में तेजी देखने को मिली है।

गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के चार मेट्रो शहरों में 17 से 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जिन चार शहरों में ये नाइट कर्फ्यू लगाए जाएंगे उनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट का नाम शामिल है। महाराष्ट्र और पंजाब के कुछ जिलों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को से ही एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है।

वहीं, पंजाब में जालंधर, नवाशहर और शाहपुर में कोरोना वायरस के ने स्ट्रेन मिलने के बाद कुल आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मोहाली, जालंधर और लुधियाना में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच सूरत में सिटी बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट में रात 10 बजे के बाद सरकारी बसों की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।

म्यूजिक वीडियो पतली कमरिया में नजर आएंगी मौनी रॉय

अभिनेत्री मौनी रॉय म्यूजिक वीडियो 'पतली कमरिया' में नजर आएंगी। डांस ट्रैक की कंपोजिशन, लिरिक्स को तनिष्क बागची ने लिखा है। मौनी ने म्यूजिक वीडियों के बारे में कहा, ''जब मैंने पहली बार ट्रैक सुना तो मैं काफी आकर्षित हुई। भारतीय और पश्चिमी संगीत के संयोजन ने मुझे जकड़ लिया, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है और यह गाना हर किसी को नाचने को मजबूर कर देगा। वीडियो दुबई में शूट किया गया है और अरविंद खैरा द्वारा निर्देशित किया गया है। गाने को शाजिया और पीयूष ने कोरियोग्राफ किया है। गायक तनिष्क बागची, सुख-ई और परम्परा टंडन हैं। गाना जल्द ही यूट्यूब पर लॉन्च होगा। मौनी ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो के साथ टीवी में अपनी पहचान बनाई और 'देवों के देव .महादेव' और 'नागिन' जैसे शो में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए याद की जाती हैं। वह अब बॉलीवुड में व्यस्त हैं।

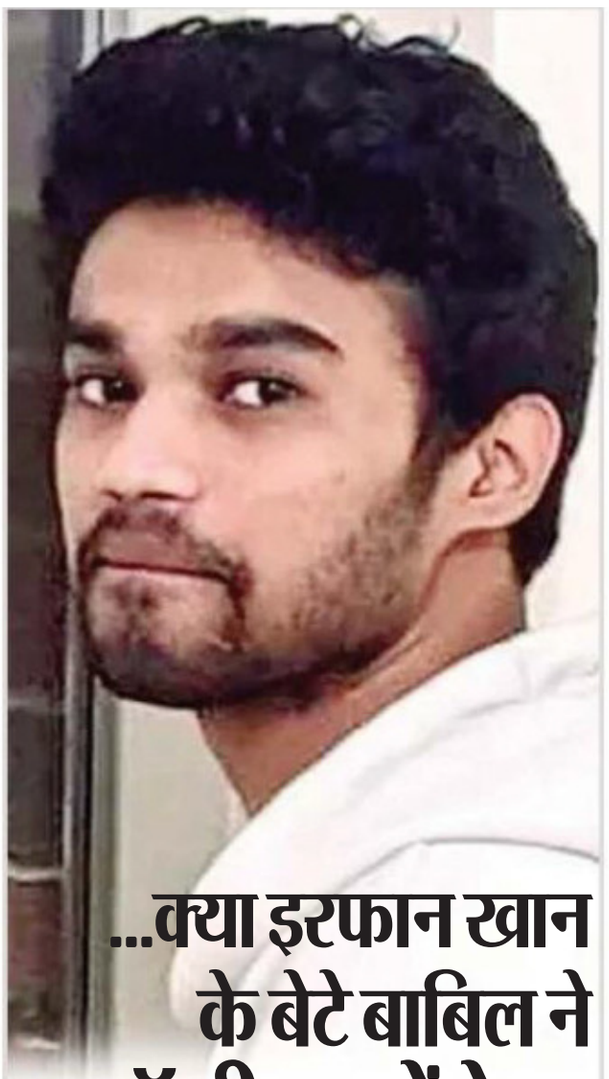

...क्या इरफान खान के बेटे बाबिल ने बॉलीवुड में डेब्यू का संकेत दिया?

दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपने पिता के बारे में पोस्ट करते हुए जल्द ही फिल्म उद्योग में शामिल होने की योजना पर संकेत दिया। जब बाबुल इस बात पर अड़े रहे कि वह अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने पिता के काम को याद किया और इंस्टाग्राम पर 'मकबूल' से इरफान के प्रशंसकों को अपनी ओर आकर्षित किया। बाबिल ने लिखा, ''मुझे पता है कि यह एक मिनट हो गया है। जब मेरे अंधविश्वास मुझे अनुमति देते हैं, तो मैं प्रकट करूंगा कि मैं किसके साथ व्यस्त हूं, लेकिन कुछ सामान है।'' कैप्शन में आगे कहा, ''वैसे भी, चूंकि मैं स्पष्ट रूप से अभिनय और 8 साल की शुरूआत में बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के भारतीय सिनेमा में अपनी यात्रा शुरू करने से बहुत भयभीत हूं, इसलिए मैं अक्सर एनएसडी और पहले की फिल्मों से बाबा के चित्रों को देखकर अपनी चिंताओं को शांत करता हूं। यहां उनके प्रशंसकों के लिए कुछ है।'' न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से दो साल की लड़ाई के बाद पिछले साल अप्रैल में इरफान की मौत हो गई। उन्हें आखिरी बार स्क्रीन पर होमी अदजानिया की 'अंग्रेजी मीडियम' में देखा गया था।

आरआरआर में सीता का किरदार निभाएंगी आलिया

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के पास इन दिनों कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। इसके अलावा उनके पास साउथ की फिल्म 'आरआरआर' भी है। एसएस राजामौली की इस फिल्म में जूनियर एनटीआर, राम चरण और अजय देवगन भी हैं। यह एक बड़ी फिल्म है और साथ ही बहुप्रतीक्षित भी। अब, फिल्म में आलिया भट्ट के रोल को लेकर जानकारी सामने आई है। फिल्म में आलिया भट्ट सीता के रूप में नजर आएंगी। आलिया का पहला लुक उनके जन्मदिन पर, यानी 15 मार्च को रिलीज होगा। फैंस इस फिल्म में आलिया को सीता के रूप में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। फिल्म के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से खबर को जारी करते हुए कहा गया, 'पूरे गौरव के साथ हमारी सीता से मिलिए। एसएस राजमौली की फिल्म बाहुबली ने पर्दे पर धमाल मचाया था। फिल्म को अपार सफलता मिली थी। जिसके बाद अब इस फिल्म के जरिए हम इस पीरियड ड्रामा में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और राम चरण को पहली बार एक साथ स्क्रीन पर देखने वाले हैं। इस फिल्म की घोषणा के बाद से ही ये फिल्म चर्चा में बनी हुई है। ये फिल्म फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा के बाद केवल 5 भाषाओं के थिएट्रिकल राइट्स के लिए अब तक 348 करोड़ से अधिक का ऑफर दर्ज किया गया है।

लोगों की नजर है अश्लील, मेरा डांस नहीं

हरियाणा की डांस सेंसेशन सपना चौधरी को अब भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक लोग जानते हैं। सपना चौधरी जल्द ही एक टीवी शो में नजर आने वाली हैं। सपना ने इस मौके पर उनके डांस को अश्लील कहने वालों को जोरदार जवाब दिया है।

अपने धमाकेदार डांस और ठुमकों से हरियाणा समेत पूरे देश को दीवाना बना देने वाली डांसर सपना चौधरी अब छोटे पर्दे पर एक नई भूमिका में नजर आने वाली हैं। सपना जल्द ही ऐंड टीवी के क्राइम शो 'मौका-ए-वारदात' में बतौर होस्ट नजर आएंगी। इस शो में अपराध की दिल दहलाने देने वाली कहानियां दिखाई जाएंगी। सपना ने इस शो, समाज और अपने करियर पर खुलकर बात की।

शो में औरतों के खिलाफ हिंसा की भी कई दास्तानें दिखाई जाने वाली हैं। आपके हिसाब से औरतों के प्रति अपराध क्यों कम नहीं हो रहे? आए दिन दिल दहलाने वाी घटनाएं सुनने को मिलती हैं.।

मैं इसमें पूरी गलती सरकार की मानती हूं। जब तक गलत हरकत करने वालों को, चाहे वो आदमी हो या औरत, सख्त सजा नहीं दी जाएगी, ये बदलाव नहीं आएगा। बेशक दो-चार लोगों को सजा हुई है, लेकिन जब तक इस तरह की सजा नहीं होगी कि लोगों के मन में डर पैदा हो। मैं कहती हूं कि अगर एक भी बंदे को ऐसी सजा मिल जाए कि लोगों के मन में डर बैठे, तो ये सब बंद हो सकता है।

अक्सर अपराध होने पर लड़की पर ही उंगली उठा दी जाती है कि उसने कपड़े ऐसे पहने या देर तक बाहर क्यों रही? आपके परफॉर्मेंसेज के बारे में भी कहा जाता है कि वे वल्गर हैं, जो औरतों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देते हैं?

देखिए, वल्गैरिटी लोगों के दिमाग में होती है। मैं तो शुरू से कहती हूं कि अगर मेरा डांस वल्गर है, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिकिनी पहनकर चलना वल्गर नहीं है? मैं तो पूरे कपड़े पहनकर डांस करती हूं। फिर, बॉलिवुड में जो आइटम डांस होते हैं, उसमें भी ऐक्ट्रेसेज काफी कम कपड़ों में डांस करती हैं, वो भी वल्गर हुआ। इस हिसाब से तो आपको हर जगह वल्गैरिटी दिखेगी। अगर आप इन चीजों से तुलना करें, तो मेरा डांस कहां से वल्गर हुआ? इनके मुकाबले तो मेरा डांस बहुत सभ्य हुआ।

आप हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग महिला रही हैं, जिसने अपने परिवार को भी संभाला और लोगों के तानों और फब्तियों का भी डटकर सामना किया। आपके हिसाब से एक सशक्त महिला की परिभाषा क्या है?

मेरे हिसाब से एक मजबूत औरत वह है, जो हर परिस्थिति में अपनी हर चीज को समेटकर रख सके, चाहे आपका परिवार हो, चाहे काम हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, उनकी नेगेटिविटी हो या उनकी पॉजिटिविटी हो। अगर आप खुद को समेटने में सक्षम हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग महिला हैं। मैं अपनी बात करूं, तो मैं खुद बहुत बार टूटी हूं और बहुत बार खुद को जोड़कर वापस उठी हूं। लेकिन जितनी बार मैं खुद को जोड़कर वापस खड़ी हुई हूं, मैंने सबकी फाड़कर रख दी। मैं ऐसे ही करती रही हूं और यही कहती रहूंगी।

अब तो आप एक मां भी हैं और मां सबसे मजबूत कही जाती है। शादी और मदरहुड के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया?

बदलाव तो कोई नहीं आया। मैं बहुत खुश हूं कि शादी के बाद भी मुझे बदलने पर मजबूर नहीं किया गया। मैं जैसी हूं, वैसे ही मुझे अपनाया गया। हां, जैसा आपने कहा, मां बनने के बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकली हूं। मेरा पांच महीने का बेटा है। मेरा बेबी ऑपरेशन से हुआ है और मैं यहां काम कर रही हूं, तो आप सोच सकती हैं कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूं। इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा मानना है कि परिवार अच्छा हो, तो लड़की और आगे जाती है।

बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद आपकी जिंदगी में कोई नया बदलाव आया?

बिग बॉस से सिर्फ मुझे पब्लिसिटी बहुत मिली, बाकी किसी चीज में तो बदलाव नहीं आया। अभी भी वैसे ही मेरे परफॉर्मेंस होते हैं, मैं वही हरियाणवी डांस करती हूं। परफॉर्मर हूं, तो स्टेज पर परफॉर्म करती हूं। इसलिए ज्यादा बदलाव तो नहीं हुआ, पर बिग बॉस से मुझे पब्लिसिटी भरपूर मिली है।

रश्मि अगडेकर ने वीडियो के जरिए बयां किया 'नगमा' का किरदार

अभिनेत्री रश्मि अगडेकर ने हाल ही में अपना फोटो शूट करवाया था और उसी दौरान ये शार्ट फिल्म फिल्माया गई थी। इस फिल्म में रश्मि, नगमा के किरदार में नजर आ रही हैं, इस वीडियो में रश्मि एक खूबसूरत एम्ब्रॉइडेड बैंगनी कुर्ती जिसके साथ वे मैचिंग दुपट्टा और चमचमाती फ्लोरल ज्वेलरी पहनी नजर आ रही हैं। वीडियो में रश्मि 'नगमा' नामक एक महिला की कहानी बता रही हैं, जोकि दिल्ली - लाहौर के भूले हुए पकवान, तहजीब, संस्कृति और दो अलग अलग जगहों का एक जैसा संबंध इस वीडियो के जरिये दर्शा रही हैं। दिल को छू लेने वाला संवाद 'लाहौर की ईद मुझे संवरती है, दिल्ली की लोहड़ी पर झूमता है लाहौर' में दो जगहों की कहानी को दर्शाया गया है और वे एक-दूसरे की परंपराओं को कैसे साझा करते हैं इस शार्ट फिल्म के जरिये अवन्ति देवदिकार ने दिखाया है, सनिका देवदिकार का कांसेप्ट है, और जय की आवाज ने इस कहानी को पूरी तरह परिपूर्ण कर दिया। रश्मि अगडेकर ने अपने अभिनय के दम पर अपनी जगह बनाई है। रश्मि अगडेकर ने ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज 'देव डीडी' से अपना वेब डेब्यू किया था और फिल्म 'अंधाधुन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। रश्मि ने कई सीरीज में अपनी छाप छोड़ी है 'रसभरी', 'इममेचुअर', के अल्हवा उनकी हालही में रिलीज हुई 'देव डीडी सीजन 2' में लेस्बियन के किरदार से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है, इसके अलावा उन्होंने कई किरदार को परदे पर बखूबी उतारा है और समीक्षकों द्वारा पसंद भी किया गया है।

रश्मि देसाई का छलका दर्द, बोलीं

टीवी एक्टर बोलकर फिल्मों में नहीं देते काम

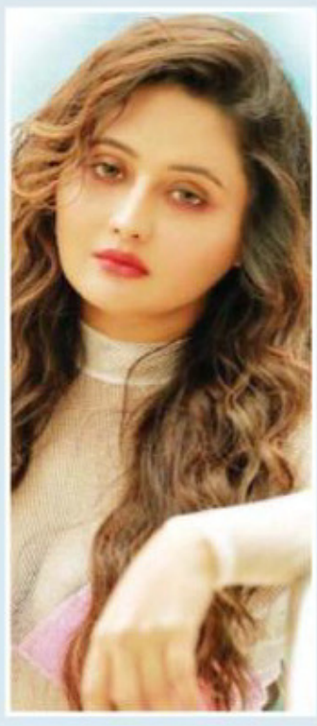

टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने हाल ही में बालीवुड पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़े कई लोग टीवी कलाकारों को बेइज्जत करते हैं। रश्मि का मानना है कि छोटे पर्दे के सितारों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। रश्मि यूं तो फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं पर असल में उन्हें लोकप्रियता टीवी से ही मिली है। एक इंटरव्यू में रश्मि देसाई ने कहा कि टीवी कलाकारों के साथ भेदभाव किया जाता है, जो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई टीवी एक्टर किसी फिल्म में रोल मांगने जाता है तो उसे काम नहीं मिलता है।

रश्मि ने कहा, फिल्मों में हमेशा नए अभिनेता और अभिनेत्री आते हैं लेकिन जब भी हम किसी फिल्म में काम मांगने जाते हैं तो हमें टीवी एक्टर बोला जाता है। हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने का पूरा हक है। हम भी बॉलीवुड सितारों के जितनी ही मेहनत करते हैं। रश्मि ने कहा, मैं भोजपुरी सहित कई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूं पर दुख होता है कि हमें टीवी एक्टर ही बोला जाता है। रश्मि के मुताबिक टीवी सितारों को सुविधा के अनुसार अच्छे प्रोजक्ट्स की पेशकश नहीं की जाती है। उन्होंने कहा, हमें समय के साथ खुद को भी आगे प्रमोट करना पड़ता है लेकिन टीवी कलाकार आज भी अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह अपमानजनक बात है। हम कलाकार हैं और हमें एक कलाकार की तरह समझना चाहिए, ना कि किसी कैटेगरी में रखना चाहिए। रश्मि देसाई ने यूं तो कई धारावाहिकों में काम किया लेकिन 'उतरन' में उनके किरदार तपस्या ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। 'बिग बॉस 13' में भी वह नजर आईं। भले ही इस शो का ताज रश्मि के सिर पर नहीं सजा पर उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला।

मैंने एक उपलब्धि हासिल की

अभिनेता इमरान हाशमी का कहना है कि आगामी थ्रिलर 'चेहरे' में अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन साझा करना उनके करियर की बड़ी उपलब्धि है। इमरान कहते हैं, ''मुझे ऐसा लगा जैसे इंतजार खत्म हो गया है। हम अमिताभ बच्चन सर को देखकर बड़े हुए हैं और इंडस्ट्री में हर कलाकार उनके साथ काम करने की इच्छा रखता है।''अभिनेता ने कहा कि बिग बी ने उनके लिए अनुशासन की भावना को प्रेरित किया है। ''अमिताभ बच्चन सर के अनुशासन को पांच दशकों से अधिक समय तक उद्योग में रहने के बाद भी देखना आश्चर्यजनक है। हमारा उद्योग बहुत अनुशासन-आधारित नहीं है, जिससे कई बार थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने मुझे प्रेरित किया है। वह समय के पाबंद हैं, हमेशा समय पर सेट पर पहुंचते हैं। यह एक प्रथा है, जिसका उन्होंने हमेशा पालन किया है।''चेहरे का निर्देशन रूमी जाफरी ने किया है और इसमें रिया चक्रवर्ती, क्रिस्टेल डिसूजा, अन्नू कपूर, धृतिमान चटर्जी, रघुबीर यादव और सिद्धांत कपूर भी हैं। फिल्म 9 अप्रैल को रिलीज होने वाली है।

इंग्लैंड के खिलाफ बराबरी के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

अहमदाबाद, (एजेंसी)। टीम इंडिया गुरुवार को यहां मेहमान टीम इंग्लैंड के साथ होने वाले चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत के साथ ही सीरीज में बराबरी पर आना चाहेगी। भारतीय टीम इस सीरीज में अभी 2-1 से पीछे है। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी जबकि दूसरे मैच में जीत के साथ भारतीय टीम ने वापसी की पर तीसरे मैच में एक बार फिर बटलर की शानदार बल्लेबाजी के कारण मेहमान टीम ने जीत दर्ज की। ऐसे में अब भारतीय टीम को यह सीरीज बचाने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे क्योंकि इस साल घरेलू धरती पर होने वाले टी20 विश्व कप को देखते हुए यह सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है।

भारत ने अब तक पहले बल्लेबाजी करते हुए जो दो मैच गंवाए हैं उसमें टीम को पावर प्ले में संघर्ष करना पड़ा है जिसके कारण टीम के अंतिम स्कोर पर असर पड़ा जबकि दोनों ही मैचों में एक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं लोकेश राहुल की खराब फार्म से भी भारतीय टीम को नुकसान हुआ है, इसके बाद भी कप्तान विराट ने राहुल पर भरोसा जताया है और कहा है कि वह रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरूआत करेंगे। ऐसे में सूर्यकुमार यादव को इस मैच में भी शायद ही जगह मिले।

वहीं इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाजों मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर ने पहले छह ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। ये दोनों विकेट से अतिरिक्त उछाल हासिल करके भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी में डालने में सफल रहे हैं। तीसरे मैच के बाद कोहली के बयान पर गौर करें तो हार्दिक पंड्या और वाशिंगटन सुंदर के साथ टीम में एक अन्य ऑलराउंडर को जगह मिल सकती है और ऐसे में पदार्पण का इंतजार कर रहे राहुल तेवतिया और अक्षर पटेल में से किसी एक को जगह मिल सकती है। कोहली ने तीसरे मैच में 77 रन की धमाकेदार पारी खेलकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया पर गेंदबाजों के नाकाम रहने से टीम को हार का सामना करना पड़ा। स्पिनर युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी अच्छी नहीं रही और मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे।

वहीं ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पंड्या की वापसी प्रभावी रही है लेकिन वह अब तक कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। चोट के बाद वापसी करते हुए पहली श्रृंखला खेल रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने किफायती गेंदबाजी की है लेकिन टीम को उनसे उम्मीद है कि वह नई गेंद से लगातार विकेट लें। ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने सबसे अधिक प्रभावित किया है जिन्होंने 6.95 प्रति ओवर की प्रभावी इकोनॉमी रेट के साथ चार विकेट लिए हैं। भारतीय टीम में अंतिम एकादश में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं दूसरी ओर मेहमान टीम इंग्लैंड भी अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी। पिछले मैच में मिली जीत से टीम का मनोबल भी बढ़ है। उसके बल्लेबाज ओर गेंदबाज भी लय में हैं। जो बटलर ने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। वहीं गेंदबाजी में आर्चर और वुड बेहतरीन फार्म में हैं। यह तीनों ही खिलाड़ी किसी भी टीम पर भारी पड़ सकते हैं।

दोनो टीमें इस प्रकार हैं:

भारतः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शारदुल ठाकुर, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, राहुल तेवतिया, इशान किशन।

इंग्लैंडः इयोन मोर्गन (कप्तान), जोस बटलर, जेसन रॉय, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, बेन स्टोक्स, मोईन अली, आदिल राशिद, रीस टॉपले, क्रिस जोर्डन, मार्क वुड, सैम कुरेन, टॉम कुरेन, सैम बिलिंग्स, जॉनी बेयरस्टॉ और जोफ्रा आर्चर।

रुस में सेंट पीटसबर्ग टेनिस में खेलते हुए डेनमार्क की क्लारा टाउसन।

डलास में एनएचएल हॉकी मुकाबले में भाग लेती हुई टाम्पा बे और ओनड्रेज पलाट।

गंभीर और लक्ष्मण भी हैं बटलर की बल्लेबाजी के प्रशंसक

अहमदाबाद, (एजेंसी)। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और स्टायलिश बल्लेबाज रहे वी वी एस लक्ष्मण ने इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की जमकर प्रशंसा की है। लक्ष्मण के अनुसार इंग्लैंड का ये बल्लेबाज 360 डिग्री शॉट लगाने वाला क्रिकेटर है। वहीं गंभीर ने भी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ बटलर को सीमित ओवरों के क्रिकेट का सबसे बेहतर बल्लेबाज बताया है। गंभीर ने कहा कि बटलर के पास बल्लेबाजी के दौरान काफी विकल्प होते हैं। फिर चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर वो रिवर्स स्वीप, लैप शॉट के अलावा कट और पुल भी अच्छी तरह से खेलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स 360 डिग्री शॉट लगाते हैं। भारत के खिलाफ बटलर की नाबाद 83 रन की पारी के दौरान भी ये नजर आया। बटलर ने इस पारी में अकेले 17 रन पुल शॉट से बनाए। उन्होंने 45 रन ऑन साइड तो 29 रन ऑफ साइड में बनाए। वो कितने निडर बल्लेबाज हैं अंदाजा इससे लगाया जा सकता है उन्होंने पहले पावर-प्ले में गेंदबाजी करने आए लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया।

मैच में बटलर ने चहल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और दो बार उनकी गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका मारा। एक बार इसी तरह का शॉट खेलने के चक्कर में कोहली ने उनका कैच भी ड्रॉप किया फिर भी बटलर की बल्लेबाजी का अंदाज नहीं बदला और वो नाबाद 83 रन की पारी खेलकर इंग्लैंड को मैच जिताने में सफल रहे। बटलर बतौर विकेटकीपर इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में एलेक स्टीवर्ट के बाद दूसरे नंबर पर हैं। स्टीवर्ट ने इंग्लैंड के लिए 59 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए थे। बटलर अब 50 बार ऐसा कर चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर मैट प्रायर हैं वो 38 बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं।

बटलर को ऐसे ही 360 डिग्री शॉट लगाने वाला क्रिकेटर नहीं कहा जाता है। वह 2014 मई के बाद के 18 महीनों में इंग्लैंड के लिए वनडे में तीन बार सबसे तेज शतक लगा चुके हैं।

डांस करते नजर आये बुमराह और संजना

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पोर्टस एंकर संजना गणेशन की शादी का वीडियो सामने आया है। बुमराह और संजना की शादी, हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। बुमराह और संजना की संगीत सेरेमनी के इस वीडियो में यह कपल जमकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। संगीत समारोह में बुमराह काले रंग की शेरवानी पहने हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं संजना ने पर्पल रंग का लहंगा पहना हुआ है। इस वीडियो में यह कपल डांस स्टेप्स को मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बुमराह का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशंसक भी इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि प्रशंसक बुमराह को पहली बार डांस करते हुए देख रहे हैं।

बुमराह और संजना की शादी 15 मार्च को 2021 को गोवा में शादी हुई थी। दोनों की अनंत कारज की रस्म गुरुद्वारे में हुई। शादी के साथ-साथ बाकी सभी समारोह भी गोवा में ही हुए। अपनी शादी की जानकारी देते हुए बुमराह और संजाना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, प्यार से प्रेरित होकर, हमने एक साथ एक नई यात्रा शुरू की है। आज हमारे जीवन के सबसे खुशी के दिनों में से एक है और हम अपनी शादी की खबरें और अपनी खुशी आपके साथ साझा करते हुए बेहद धन्य महसूस कर रहे हैं।

एथलीट श्रीशंकर ने ओलंपिक टिकट हासिल किया

पटियाला, (एजेंसी)। लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। श्रीशंकर ने पटियाला में जारी फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 8.26 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बनाने के साथ ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया।

लंबी कूद के लिए ओलंपिक क्वालीफिकेशन का स्तर 8.22 मीटर है। इस खिलाड़ी ने पांचवें प्रयास में 8.26 मीटर की छलांग लगाकर अपने राष्ट्रीय रिकार्ड में सुधार भी किया है। यह रिकार्ड उन्होंने 2018 में 8.20 मीटर की छलांग लगाकर बनाय था। श्रीशंकर ने पहले चार प्रयास में 8.02 मीटर, 8.04 मीटर, 8.07 मीटर और 8.09 मीटर की दूरी तय करने के बाद पांचवें प्रयास में 8.26 मीटर की छलांग लगाई हालांकि वह अंतिम प्रयास में नाकाम रहे। वहीं एक अन्य खिलाड़ी मोहम्मद अनीस याहिया ने आठ मीटर में रजत जबकि कर्नाटक के एस लोकेश ने 7.60 मीटर की छलांग के साथ ही कांस्य पदक अपने नाम किया है।

एथलेटिक्स में इससे पहले भारत की ओर से पैदल चाल में पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा में केटी इरफान, संदीप कुमार और राहुल रोहिला तथा महिलाओं की 20 किलोमीटर स्पर्धा में भावना जाट और प्रियंका गोस्वामी ने क्वालीफाई किया था।

बीकेटी करेगी आईपीएल टीमों को प्रयोजित

नई दिल्ली, (संवाददाता)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र में टायर निमार्ता कंपनी बालकृष्णा इंडस्ट्रीज (बीकेटी टायर्स) सात आईपीएल टीमों को प्रायोजित करेगी। बीकेटी टायर्स ने अपने एक बयान में कहा है कि गत चैंपियन मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और रास्थान रॉयल्स के आधिकारिक टायर साझेदार होंगे। बीकेटी ने पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के साथ साझेदारी की है जबकि बाकी छह टीमों के साथ अपने पिछले साल की ही साझेदारी को आगे बढ़ाया है।

स्प्लिट कप्तानी भारतीय टीम के लिए सही नहीं : लक्ष्मण

मुम्बई, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टायलिश बल्लेबाज रहे वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है स्प्लिट कप्तानी (अलग-अलग प्रारुप में अलग-अलग कप्तान) का तरीका भारतीय टीम के लिए सही नहीं रहेगा। लक्ष्मण ने माना है कि विराट कोहली के नहीं होने पर वनडे और टी20 क्रिकेट के उप कप्तान रोहित शर्मा आगे बढ़कर टीम की कप्तानी करते हैं। कई क्रिकेट विशेषज्ञ कप्तानी के मामले में रोहित को मिली सफलता से उत्साहित भी हैं। कोहली को तीनों फॉर्मेट में करिश्माई कप्तान माना जाता है। लक्ष्मण ने कहा कि इसके बाद भी विराट और रोहित के बीच कप्तानी की जिम्मेदारियों को साझा करना ठीक नहीं रहेगा।

लक्ष्मण ने तीनों प्रारुपों के लिए विराट को एक आदर्श कप्तान बताया है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि जब तक आपका कप्तान कप्तानी का बोझ नहीं महसूस करता, तब तक वह कप्तानी की जिम्मेदारियां का आनंद उठाता है। तब तक वह अपने प्रदर्शन से कोई समझौता नहीं करता। उसे सभी प्रारुपों में कप्तान रहने दें।

उन्होंने कहा, इंग्लैंड में स्प्लिट कप्तानी काम करती है, क्योंकि जो रूट सीमित ओवर क्रिकेट में नहीं खेलते और ऑयन मोर्गन वनडे में कप्तानी करते हैं, लेकिन वह टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। यदि कोई तीनों फॉर्मेट में टॉप परफॉर्मर है तो टीम का एक ही कप्तान होना चाहिए। लक्ष्मण ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया को परिभाषित करने का श्रेय विराट को दिया। लक्ष्मण ने जोर देकर कहा कि कोहली की कार्यशैली और पेशेवराना रुख पूरी पीढ़ी को प्रेरित करता है।

ओलंपिक मशाल रिले के दौरान बरती आयेगी सभी सावधानियां : आयोजक

टोक्यो, (एजेंसी)। आगामी टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने कहा है कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए अगले सप्ताह 25 मार्च से शुरू होने वाली ओलंपिक मशाल रिले के दौरान पूरी सावधानी बरती जाएगी। आयोजकों के अनुसार यह सतर्कता बरतने पर इसलिए जोर दिया जा रहा है जिससे ओलंपिक आयोजन पर कोई खतरा न हो।ओलंपिक का आयोजन एक साल 23 जुलाई से होगा। आयोजकों ने शुरू होने वाली मशाल रिले का लक्ष्य लोगों में खेल के आयोजन के प्रति उत्साह है। मशाल रैली की शुरूआत जापान के पूर्वोत्तर क्षेत्र फुकुशिमा प्रांत से होगी और अगले चार महीने में लगभग 10,000 धावक इसे लेकर पूरे जापान मेंजाएंगे। आयोजन समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तोशिरो मुतो ने कहा, ओलंपिक मशाल रिले का उद्देश्य उत्साह बढ़ाना है। हमें उमंग को बढ़ाने के साथ कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए चीजों को संतुलित करने की जरुरत है। यह रिले जापान से सभी 47 प्रांतों से होकर गुजरेगी जिससे कोविड-19 के फैलने का खतरा है। इस दौरान रिले देखने आने वाले खेल प्रशंसकों को सामाजिक दूरी बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी गयी है।

विराट ने राहुल का बचाव करते हुए उसे चैंपियन बल्लेबाज बताया

अहमदाबाद, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाज लोकेश राहुल के खराब प्रदर्शन के बाद भी उनका बचाव किया है और कहा है कि वह टीम के लिए पहली पसंद बने रहेंगे। विराट के इस फैसले से प्रशंसकों को हैरानी हुई है क्योंकि यह तीसरे बार है जब राहुल खाता तक नहीं खोल पाये हैं। इसमें भी दो बार वह साफ बोल्ड हुए। इसके बाद से ही उनकी तकनीक पर भी सवाल उठ रह हैं। इसके बाद भी विराट ने राहुल का बचाव करते हुए उसे चैंपियन खिलाड़ी करार दिया और कहा कि वह टीम की पहली पसंद रहेगा।

भारत को तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। राहुल इस मैच में खाता तक नहीं खोल पाए। राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ बीते तीन मैचों में 1, 0, 0 का स्कोर बनाया है। उनका मानना है कि यह कुछ गेंदों की बात है। उन्होंने कहा, मैं भी दो दिन पहले तक खराब दौर से गुजर रहा था। राहुल एक चैंपियन खिलाड़ी है। वह शीर्ष क्रम में रोहित के साथ हमारा अहम खिलाड़ी है। इस फॉर्मेट में पांच-छह गेंदों की बात है।

इस मैच में कोहली ने 46 रन की अपनी पारी से भारत को मुश्किल से निकाला। उन्होंने कहा कि नई गेंद का सामना करना मुश्किल था। खास तौर पर मार्क वुड को जो लगातार 145-150 की गति से गेंदबाजी कर रहे थे। कोहली ने कहा, आप ऐसी पारी खेलना चाहते हैं जिससे टीम को मदद मिले। नई गेंद के खिलाफ बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनके गेंदबाज सही क्षेत्र में गेंदबाजी कर रहे थे।

न्यूजीलैंड में अमेरिका कप फाइनल में भाग लेती हुई नौकाएं।

सूर्यकुमार को शामिल नहीं किये जाने से विराट पर भड़े गंभीर

नई दिल्ली, (संवाददाता)। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव को तीसरे टी20 मैच में अंतिम ग्यारह में शामिल नहीं किये जाने को लेकर कप्तान विराट कोहली की जमकर आलोचना की है।

गंभीर ने कहा कि किसी खिलाड़ी को बिना आजमाये ही बाहर कर देना ही समझ से परे है।

सूर्यकुमार ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से डेब्यू किया था हालांकि उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था। भारत ने मैच सात विकेट से आसानी से जीत लिया था पर हैरानी की बात यह रही कि अगले ही मैच में इस बल्लेबाज को बिना किसी कारण के टीम से बाहर कर दिया गया। सूर्यकुमार की जगह लोकेश राहुल को शामिली किया गया जो लगातार नाकाम रहे हैं और तीसरी बार भी खाता खोले बिना ही पेवेलियन लौट गये।

गंभीर ने कहा है कि टीम इंडिया अपनी बैंच स्ट्रैंथ को नहीं आजमा रही है जो सही नहीं है। गंभीर ने कहा, आपने सूर्यकुमार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितना देखा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भी चोटिल न हो लेकिन अगर ऐसा हो जाए और आपको किसी को नंबर चार या पांच पर बल्लेबाजी करवानी हो तो आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा।

गंभीर ने कहा, कम से कम जिसे आपने टीम में शामिल किया है उसे देखिए तो सही। उसे तीन-चार मैचों में मौका दीजिए। इसके बाद ही उसको लेकर कोई फैसला कीजिए। अगर वह अच्छा करते हैं तो आपके पास ऐसे खिलाड़ी का बैकअप हो जाएगा जो पहले से नंबर चार पर बल्लेबाजी कर रहा है। अगर आपने किसी को सीरीज में शामिल किया है तो उसे मौके दीजिए और देखिए कि वह भविष्य में आपको क्या दे सकता है। हम तैयारियों की बात करते रहते हैं पर जिस प्रकार खेला जा रहा है उससे यह विश्व कप की कोई तैयारी नहीं लगती क्योंकि पहले से ही खेल रहे खिलाड़ियों को बदल-बदलकर अवसर दिये जा रहे हैं।